नई दिल्ली
मंगलवार
24 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 81
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अख्तरुल...पेज-05

DELHIN/2014/58158

विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सत्तापक्ष...पेज-08

एक नजर

व्हाट्सऐप वेब के इस्तेमाल में बरतें सावधानी, हर सत्र के बाद लॉगआउट करने की सलाह



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने व्हाट्सऐप वेब के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर परामर्श जारी करते हुए उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सऐप वेब का सक्रिय सत्र कुछ परिस्थितियों में उपयोगकर्ता के खाते तक अनधिकृत पहुंच का माध्यम बन सकता है। इसके जरिए साइबर अपराधी संदेश पढ़ने, उपयोगकर्ता की पहचान से दूसरों को संदेश भेजने और संपर्कों तथा समूहों की बातचीत तक पहुंच बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (एनसीटीएयू) के परामर्श के अनुसार व्हाट्सऐप वेब के दुरुपयोग से धोखाधड़ी, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी साइबर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में विशेष रूप से कार्यालयों, साझा प्रणालियों, सार्वजनिक कंप्यूटरों और दूसरे व्यक्तियों की पहुंच वाले उपकरणों पर इसका इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। परामर्श में सरकारी, संगठनात्मक, वित्तीय, गोपनीय और अन्य संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही, जरूरत नहीं होने पर व्हाट्सऐप वेब को लगातार लॉगइन रखने से बचने को कहा गया है। आई4सी ने उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक सत्र पूरा होने के बाद व्हाट्सऐप वेब से अनिवार्य रूप से लॉगआउट करने की सलाह दी है। परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि केवल ब्राउजर की विंडो या टैब बंद कर देना लॉगआउट करने के समान नहीं है। यदि अस्थायी रूप से व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो किसी भरोसेमंद कंप्यूटर पर इनकॉग्निटो या निजी ब्राउजिंग मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ब्राउजर बंद करने से पहले मैन्युअल रूप से लॉगआउट करना भी जरूरी है। परामर्श में साइबर कैफे, सार्वजनिक कियोस्क, होटल के बिजनेस सेंटर, उधार लिए गए कंप्यूटर और अन्य अविश्वसनीय प्रणालियों पर व्हाट्सऐप वेब में लॉगइन नहीं करने को कहा गया है। इसके अलावा, खाते से अपने आप संदेश भेजे जाने, संपर्कों की ओर से असामान्य जवाब मिलने या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। आई4सी ने उपयोगकर्ताओं को अपने उपकरणों के ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखने तथा संदिग्ध डाउनलोड, अनजान फाइलों, क्रैक सॉफ्टवेयर और अविश्वसनीय अटैचमेंट से बचने को भी कहा है। परामर्श में संगठनों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि आधिकारिक और संवेदनशील कार्यों के लिए कार्यालयों में व्हाट्सऐप वेब के इस्तेमाल से बचें। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सतर्क रहें, प्रत्येक सत्र के बाद लॉगआउट करें और अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखें।

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देंगीः मोदी



नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प गुरुओं की प्रेरणा और उनके आदर्शों की शक्ति से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने सिख परंपराओं और विरासत को प्रकाश पुंज बनाकर आगे बढ़ाने तथा गुरु साहिब की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिल्ली के लोक निवास में आयोजित शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सिख समुदाय के संत-महात्मा, ज्ञानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस आयोजन में शामिल होने का अवसर देने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गुरबाणी का प्रत्येक शब्द और कीर्तन की प्रत्येक धुन केवल संगीत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक साधना है। यह ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने जैसा अनुभव है। जब भी उन्हें ऐसे आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलता है, वह संगत और कीर्तन में अवश्य उपस्थित होते हैं। मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव की शिक्षाओं में 'किरत करो, वंड छको और नाम जपो' का संदेश उनके जीवन का सहज हिस्सा रहा है। गुरुद्वारों में मत्था टेकना, गुरबाणी में डूबकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना, सेवा का सुख लेना और लंगर छकना बचपन से उनके जीवन का हिस्सा रहा है। संगठन के कार्यकर्ता के रूप में भी यह सिलसिला निरंतर जारी रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पंजाब में भी काफी समय बिताया है और वह समय उनके जीवन की सबसे खास स्मृतियों में शामिल है। गुरु कृपा से उन्हें सिख संतों की संगत का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर भी अनेक सिख संतों और ज्ञानियों की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित संतों और ज्ञानियों को नमन करते हुए सिख समुदाय के सभी लोगों का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ एक और पवित्र स्मृति जुड़ी है। इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दिल्ली की इसी धरती पर देश की पहचान, आस्था, विश्वास और मूल्यों की रक्षा के लिए गुरु साहिब ने अपना बलिदान दिया था। साढ़े तीन सौ वर्ष बीतने के बाद भी उनकी शहादत की प्रेरणा भारत की मिट्टी और देश के जन-जन में समाई हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और उसकी संस्कृति के लिए सब कुछ न्योछावर करने का जज्बा पूरी सिख परंपरा का पर्याय रहा है। भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत भी हमें इसी भावना की याद दिलाती है। स्वतंत्रता संग्राम में भी यह परंपरा निरंतर जारी रही। उन्होंने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार तेजा सिंह समुंदरी को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। इस वर्ष उनकी शहादत के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

मोदी ने कहा कि भारत ने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी झेली, लेकिन कठिन दौर में भी हमारे गुरुओं ने देश की रक्षा की ज्योति जलाए रखी। आज जब देश के सामने विकसित भारत का बड़ा संकल्प है, तब यह यात्रा गुरुओं की प्रेरणा और उनके आदर्शों की शक्ति से ही पूरी हो सकती है। इसलिए सिख परंपराओं और सिखी की विरासत को प्रकाश पुंज बनाकर आगे रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने पूरी आस्था के साथ इस दायित्व को निभाने का प्रयास किया है। गुरु गोबिंद सिंह का 350वां प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व देश और विदेशों में मनाया गया। इस दौरान स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए, विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं और देशभर में गुरबाणी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले में राष्ट्रीय आयोजन किया गया था। इसी भावना के साथ इस समय उनकी 350वीं शहादत वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महीने बाद 26 दिसंबर को देश वीर बाल दिवस मनाएगा। सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है, ताकि वीर साहिबजादों की शहादत और माता गुजरी की संकल्प शक्ति, साहस एवं शौर्य की अमर गाथा देश की नई पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। बच्चे जब उस दौर की परिस्थितियों और साहिबजादों के बलिदान के बारे में जानेंगे, तो इससे उनके भीतर देश के प्रति समर्पण का भाव विकसित होगा।

भारत-नेपाल को देगा 24 हजार करोड़ की सहायता, 8 समझौतों के साथ सरयू-कमला एक्सप्रेस की शुरुआत



नई दिल्ली,एजेंसी। भारत बाढ़ से प्रभावित नेपाल को दीर्घकालिक विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये की विकास सहायता पैकेज देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच गुरुवार को वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन अयोध्या से जनकपुर (नेपाल) जाएगी। दोनों देशों ने साझा भविष्य को नई दिशा देने के लिए एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के अपने-अपने संकल्पों को पूरा करने का ब्लू-प्रिंट है। इसके अलावा बनबासा में नए आईसीपी (इंट्राक्लोजर कंट्रोल) और भैरहवा, सुनाउली और दोधारा चांदनी में आईसीपी के निर्माण में प्रगति की आधारशिला रखी गई। धारचूला (भारत) और दार्चुला (नेपाल) के बीच नए सीमा पार मोटर योग्य पुल का उद्घाटन किया गया। लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना (669 मेगावाट) की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन (एमएपीएल) के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया गया। प्रस्तावित सिलीगुड़ी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन के झापा स्थित पेट्रोलियम टर्मिनल की आधारशिला रखी गई।

दोनों देशों के बीच आज आठ समझौता पर भी सहमति बनी है। यह समझौते अपराध जांच, पुलिस प्रशिक्षण, नौकरशाहों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आयुर्वेद और परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग, दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग हेतु उपग्रह संचार (सैटकॉम) नेटवर्क की स्थापना, सतत शहरी विकास से जुड़े तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य एवं दवा क्षेत्र में सहयोग और पशुधन और मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन्द्र शाह की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत का रिश्ता पड़ोस का नहीं बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का है। हमारी खुशियां और चुनौतियां साझा हैं और हम प्रगति के साथी तथा मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा हैं। भगवान राम और सीता को दोनों देशों की साझा सभ्यता का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नेपाल के बिना हमारे धाम और हमारे राम दोनों अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन सेवा ने भारत-नेपाल के पवित्र रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ दिया हैं। दोनों देश बौद्ध और शिव-शक्ति से जुड़े तीर्थ स्थलों के बीच संपर्क सुविधाएं बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। नेपाल की नदियों में स्वच्छ ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और भारत का बड़ा बाजार इन संभावनाओं को नेपाल की प्रगति का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि हम नेपाल में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर, इनोवेशन हब और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक ऑफशोर कैंपस स्थापित करेंगे।

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली में केवल बीएस-VI वाहनों को चलाने की अनुमति देने पर विचार



नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों में गहराने वाले वायु प्रदूषण के संकट को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में केवल बीएस-VI मानक वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान 15 साल से अधिक पुरानी एक वोल्वो कार के मालिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना ने अपनी अर्जी रखी। उन्होंने दलील दी कि न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर 2025 में बीएस-IV और उससे नए वाहनों को केवल उम्र के आधार पर जब्त करने से अंतरिम राहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर उनके मुवक्किल की गाड़ी को ईंधन देने से मना किया जा रहा है। इस अर्जी पर राहत मांगने के जवाब में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम दिल्ली में केवल बीएस-VI वाहनों को ही अनुमति देना चाहते हैं, भले ही पूरे एनसीआर में ऐसा तुरंत संभव न हो। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह रोकने के लिए 5 साल की एक दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि फल, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर बड़े गोदाम बनाए जाने चाहिए, जहां से इलेक्ट्रिक या स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों के जरिए शहर के भीतर सामान की आपूर्ति की जा सके। प्रदूषण नियंत्रण में पड़ोसी राज्यों की ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य संबंधित राज्यों को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जब केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का जिक्र किया, तो बेंच ने कहा कि इस साल नवंबर में दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में जाने से बची रही, तो इसका मुख्य श्रेय अनुकूल हवाओं और प्रकृति के सौभाग्य को जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल मौसम के भरोसे नहीं बैठा जा सकता और प्रदूषण रोकने के लिए कड़े एवं स्थायी कदम उठाने होंगे।

भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कियाः शिवराज चौहान



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और अत्यंत गरीबी की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह इस असाधारण उपलब्धि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, कृषि अनुसंधान , भूमि संसाधन तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के योगदान पर मंथन करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए आज नई दिल्ली स्थित आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस संयुक्त कार्यशाला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी शामिल रहे। कार्यशाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, आईसीएआर, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो उपलब्धि हासिल की है, वह सचमुच असाधारण, अद्भुत और अकल्पनीय है। स्वयं वर्ल्ड बैंक ने माना है कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेजी से गरीबी कम नहीं हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कहने को 50 करोड़ का आंकड़ा आसान लगता है, लेकिन यदि हम तुलना करें तो अमेरिका की कुल आबादी लगभग 30 करोड़ है और पूरे यूरोप की आबादी भी मिला दें तो शायद 50 करोड़ न हो। इतने विशाल जनसमूह का गरीबी की रेखा से ऊपर उठना एक ऐतिहासिक घटना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनका विजन और उनका परिश्रम तो है ही, साथ ही दोनों मंत्रालयों के हर अधिकारी और कर्मचारी की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 92वीं बैठक में समुद्री वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर



नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 92वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन्यजीव और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ विकास परियोजनाओं और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान वन्यजीव सप्ताह-2026 की रिपोर्ट पर विचार किया गया। इस वर्ष वन्यजीव सप्ताह 'वन्यजीवों के आवासों को जोड़ना, उन्हें समृद्ध बनाना' विषय पर मनाया गया था। भूपेंद्र यादव ने इस दौरान किए गए संरक्षण प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और जमीनी स्तर पर प्रभावी परिणाम देने वाली पहल पर जोर दे रही है। इन पहलों में पश्चिम बंगाल के बक्सा में बाघों को दोबारा बसाना, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को जंगल में छोड़ना और प्रोजेक्ट चीता का तीसरे स्थान तक विस्तार करना शामिल है। इस मौके पर भूपेन्द्र यादव ने वन्यजीव सप्ताह के दौरान चयनित पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और वन्यजीव संरक्षण में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।

दिल्ली भाजपा 26 नवम्बर को संविधान गौरव दिवस समारोह करेगी आयोजित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि



नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली ईकाई 26 नवबंर को सिविक सेंटर में 'संविधान गौरव दिवस समारोह' का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रुप में शामिल होंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस समारोह का आयोजन संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने और संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि समारोह में दिल्ली के बुद्धिजीवी वर्ग को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के सभी सांसदों एवं आमंत्रित बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद भी कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किए। मल्होत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस नेता संविधान की छोटी प्रति जेब में रखकर बात-बात पर संविधान की शपथ लेते हैं, इन लोगों ने संविधान की मूल भावना की हत्या कर दी। 1975 में इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता रहते प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही तरह आम आदमी पार्टी भी अराजक पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ राजपथ (कर्तव्य पथ) पर धरना दिया, बल्कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद भी बहुत दिनों तक इस्तीफा देने से इनकार किया।

हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली भाजपा 'संविधान गौरव अभियान' के तहत दिल्ली एवं देशवासियों को संविधान के प्रति जागरूक कर रही है और इस अभियान का उद्देश्य है कि डॉ. अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करें - जहां सामाजिक समरसता हो, समानता हो और हर नागरिक को न्याय मिले। मल्होत्रा ने कहा कि 'संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आकांक्षाओं का दस्तावेज़ है।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने संविधान के आदर्शों को व्यवहार में उतारा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक में अतिक्रमण पर सख्त, दोबारा कब्जा हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार



नई दिल्ली। चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक गरिमा को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चांदनी चौक और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी रखा जाए। साथ ही, जिन स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं, वहां दोबारा अतिक्रमण न होने पाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हटाए गए स्थानों पर फिर से कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल अतिक्रमण हटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थानों पर दोबारा अवैध कब्जे न हों। इसके लिए नगर निगम और दिल्ली पुलिस को नियमित निगरानी और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एवं इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने 20 नवंबर को निगम, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि अतिक्रमण पुरानी दिल्ली के विकास में बड़ी बाधा है, इसलिए सभी विभागों को मिलकर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से रविवार को पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी सहित कई प्रमुख स्थानों पर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और आम लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाना है। अभियान के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा कब्जे की कोशिश को तत्काल रोका जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों से न केवल लोगों के आवागमन में परेशानी होती है, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में किसी भी विभाग की लापरवाही, उदासीनता या अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक गौरव लौटाना सरकार की प्राथमिकता है। यह क्षेत्र देश की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ियों से संजोई गई परंपराओं का प्रतीक है। सरकार का प्रयास है कि पुरानी दिल्ली को उसकी ऐतिहासिक गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाए, जहां विरासत भी सुरक्षित रहे और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त सड़कें, सुगम आवागमन, व्यवस्थित बाजार और स्वच्छ सार्वजनिक स्थल इस बदलाव की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और अतिक्रमण हटाए गए स्थानों पर दोबारा अव्यवस्था नहीं लौटने दी जाएगी।

दिल्ली की कदीमी मस्जिद मामले में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर स्थित ऐतिहासिक 'कदीमी मस्जिद' को हटाए जाने के मामले पर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अनीश दयाल की सिंगल बेंच ने इस विवाद से जुड़ी दो याचिकाओं (एक मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति और दूसरी एक नमाजी मोहम्मद यासिर की) पर एक साथ सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने इसके साथ ही अगली सुनवाई जनवरी, 2027 के लिए तय कर दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता तुषार सन्नू ने बोर्ड के 17 नवंबर के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना जनहित से जुड़ी है, लेकिन पुनर्विकास योजना में मस्जिद को बनाए रखने की संभावनाओं पर तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। बोर्ड ने दलील दी कि यह मस्जिद 149 साल से भी अधिक पुरानी अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और 15 अगस्त, 1947 को भी इसका धार्मिक स्वरूप यही था, इसलिए इसे 'उपासना स्थल अधिनियम, 1991' की धारा 4(1) के तहत संरक्षण प्राप्त है। बोर्ड ने केंद्र सरकार के इस तर्क को भी खारिज किया कि सरकारी परिसर 'धर्मनिरपेक्ष' होने के कारण वहां कोई स्थायी धार्मिक ढांचा नहीं रह सकता। मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से आग्रह किया कि मामले के लंबित रहने तक नमाजियों के मस्जिद में प्रवेश पर कोई रोक न लगाई जाए। इस पर केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय का पक्ष रख रहे एएसजी चेतन शर्मा ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मेरे होंठ सिले हुए हैं ...'। इस दौरान जस्टिस अनीश दयाल ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि जब तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक मस्जिद में जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। दूसरे याचिकाकर्ता (नमाजी) मोहम्मद यासिर की ओर से अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने 1945 के एक पंजीकृत समझौते का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए और समझौते का उल्लंघन साबित किए केंद्र सरकार 266 वर्ग गज की इस मस्जिद को नहीं गिरा सकती। न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से पेश हुए सीजीएससी निशांत गौतम को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता मोहम्मद यासिर के प्रतिवेदन पर अपना जवाब दाखिल करें। मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति को भी वक्फ बोर्ड के हलफनामे पर अपना जवाब देने के लिए समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से स्थायी अधिवक्ता सौरभ सेठ उपस्थित रहे।

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आठ साल पुराने मानहानि केस में गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले 31 अक्टूबर को न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसे तामील नहीं कराया जा सका। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

अदालत में 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विकास पांडे की ओर से पेश वकील सक्षम शर्मा ने कहा था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और काकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे, लेकिन अब वे भारत छोड़ चुके हैं। इसके पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि ध्रुव राठी के खिलाफ जारी ताजा समन तामील तो किया गया, लेकिन ध्रुव राठी के परिसर में ताला लगा हुआ मिला। उसके बाद ध्रुव राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।

तब उनके आवास के बाहर समन चस्पा कर दिया गया। न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई, 2019 में समन जारी किया गया था और शिकायतकर्ता लगातार समन जारी करवाने की कोशिश कर रहा था।

महापौर ने गुरु पर्व के नगर कीर्तन मार्ग का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले नगर कीर्तन की तैयारियों के लिए दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और निगमायुक्त संजीव खिरवार ने सोमवार को गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से फतेहपुरी चौक तक नगर कीर्तन मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुरानी दिल्ली क्षेत्र की उपायुक्त कनिका सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

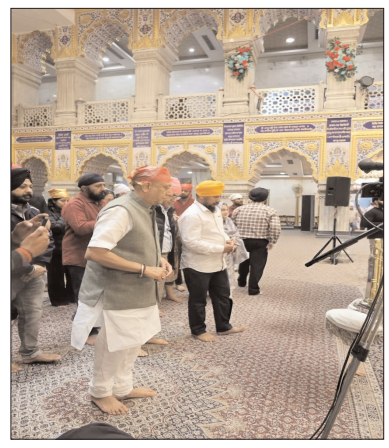

महापौर एवं निगमायुक्त ने पूरे मार्ग पर सफाई व्यवस्था, कचरा उठाने और स्वच्छता से जुड़े कार्यों की स्थिति देखी। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर कीर्तन मार्ग पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जहां भी कोई कमी नजर आए, उसे तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय रहते तैयारियां पूरी करने को कहा। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि गुरु पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ-साथ दिल्ली की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नगर कीर्तन के इस मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसलिए यहां स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के आह्वान और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम राजधानी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। हालांकि, कुछ छोटी-मोटी कमियां सामने आई हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निगम अधिकारी पूरी तत्परता से काम करेंगे और नगर कीर्तन स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न होगा। निरीक्षण के बाद महापौर प्रवेश वाही और निगमायुक्त संजीव खिरवार ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में माथा टेका और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

गांधी नगर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग

नई दिल्ली,एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित नेहरू गली में सोमवार सुबह एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक, आज सुबह 8:55 बजे गांधी नगर की नेहरू गली में एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां, एक अन्य दमकल वाहन और क्यूआरवी मौके पर भेजी गई। यह दुकान एक चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। इमारत ग्राउंड फ्लोर के अलावा तीन मंजिल की है और करीब 35 वर्ग गज क्षेत्र में बनी हुई है। मौके पर दमकल की कुल 11 गाड़ियां पहुंची। दमकलकर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। कपड़ों का सामान होने के कारण आग फैलने की आशंका थी। इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों और दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

पुरानी रंजिश में युवक को बाइक पर अगवा कर चाकू से हमला, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को बाइक पर अगवा कर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों ने युवक को पहले बाइक पर बैठाकर ब्रह्मपुरी की गली में ले गए। वहां तीनों ने मिलकर उस पर चाकू और धारदार हथियार से कई वार किए। घायल युवक की गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया है। तीसरा आरोपित अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक, घायल असलम (22) 19 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे वह जाफराबाद में राशिद बिरयानी के पास मौजूद था। इसी दौरान बाइक पर अब्बास उर्फ छम्मिया, समीर उर्फ बब्बू और शाकिर वहां पहुंचे। तीनों असलम को पहले से जानते थे। आरोप है कि उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अब्बास ने करीब डेढ़ साल पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए धमकी दी। उसका आरोप था कि असलम ने पहले उस पर ब्लेड से हमला किया था। असलम ने वहां से भागने की कोशिश की तो तीनों ने उसे पकड़ लिया। अब्बास ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जबकि बाकी दोनों उसे जबरन बाइक पर बैठाकर ब्रह्मपुरी की गली में ले गए। वहां तीनों ने उस पर हमला कर दिया। कई वार लगने से असलम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। घायल किसी अज्ञात दोपहिया वाहन चालक की मदद से जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचा। वहां से उसे आगे के इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। एसएचओ राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 20 नवंबर को मोहम्मद अब्बास उर्फ छम्मिया (26) को गिरफ्तार किया। इसके बाद 22 नवंबर को समीर (23) को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद किया है। दोनों आरोपितों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस अब फरार तीसरे आरोपित शाकिर की तलाश कर रही है।

एमसीडी ने मनाया 'भाषा-संगम 2026', हिंदी-उर्दू-पंजाबी की साझी विरासत का हुआ उत्सव

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे



नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के राजभाषा विभाग ने सोमवार को सिविक सेंटर के केदारनाथ साहनी सभागार में 'भाषा-संगम 2026' का आयोजन किया गया। हिंदी, उर्दू एवं पंजाबी भाषा महोत्सव के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में भाषाई विविधता, साहित्यिक समृद्धि और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की पावन संध्या को समर्पित रहा। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, उपमहापौर एवं हिंदी समिति की अध्यक्ष मोनिका पंत तथा हिंदी समिति की उपाध्यक्ष मनीषा, अतिरिक्त आयुक्त ऐ के मिश्रा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता। भाषा लोगों को जोड़ने, विचारों को साझा करने और एक-दूसरे की संस्कृति को समझने का माध्यम है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं का भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। इन भाषाओं की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं, लेकिन इनके बीच आपसी जुड़ाव और साझी विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान करना चाहिए और भाषाई विविधता को अपनी ताकत बनाना चाहिए। ऐसे आयोजन समाज में आपसी सद्भाव, सम्मान और एकता की भावना को मजबूत करते हैं।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में एकता में निहित है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी जैसी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन भाषाओं के साहित्य, कविता, संगीत और परंपराओं ने समाज को हमेशा जोड़ने का काम किया है। 'भाषा-संगम' जैसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपमहापौर एवं हिंदी समिति की अध्यक्ष मोनिका पंत ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी अभिव्यक्ति, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम है। उर्दू की नजाकत और पंजाबी की जीवंतता हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाती हैं।

एम्स की कार्यशाला में बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज की शुरुआती पहचान पर जोर

नई दिल्ली,एजेंसी। बच्चों और किशोरों में टाइप-1 डायबिटीज की समय पर पहचान, बेहतर उपचार और जीवनभर प्रभावी प्रबंधन को लेकर एम्स और एचआरआईडीएवाई (हृदय) ने सोमवार को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया। 'बियॉन्ड डायग्नोसिस: लिविंग वेल विद टाइप-1 डायबिटीज एट होम, इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी प्रतिनिधियों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभारी उप आयुक्त डॉ. शोभना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। एम्स के निदेशक एवं एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग के प्रमुख प्रो. निखिल टंडन तथा हृदय की कार्यकारी निदेशक प्रो. मोनिका अरोड़ा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए केवल बीमारी की पहचान और उपचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बीमारी को समझने और उसका आत्मविश्वास के साथ प्रबंधन करने में सक्षम बनाना भी जरूरी है। इसके लिए परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 2.0 के वर्ष 2026 के संचालन दिशा-निर्देशों में टाइप-1 डायबिटीज की स्क्रीनिंग को शामिल किया जाना रहा। इन दिशा-निर्देशों में बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानने पर जोर दिया गया है। इसके लिए '4T' संकेतों का उल्लेख किया गया है। इनमें टॉयलेट (बार-बार पेशाब आना), थर्स्टी (अधिक प्यास लगना), टायर्ड (थकान महसूस होना) और थिनर (वजन कम होना) शामिल हैं। इन लक्षणों की पहचान के साथ मौके पर ही ब्लड ग्लूकोज जांच और बच्चों को जिला अस्पतालों के गैर-संचारी रोग (एनसीडी) क्लीनिक में रेफर करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

नितिन नवीन का डीपफेक वीडियो वायरल, दिल्ली भाजपा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कथित फर्जी बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में दिल्ली भाजपा ने दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि 22 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित जनसभा के वास्तविक वीडियो के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक तकनीक के माध्यम से छेड़छाड़ कर भ्रामक वीडियो तैयार किया गया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत सौंपी। प्रतिनिधिमंडल में सांसद प्रवीन खंडेलवाल, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, प्रदेश मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और प्रदेश लीगल प्रमुख अधिवक्ता संकेत गुप्ता शामिल रहे।

शिकायत के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में समाचार एजेंसी एएनआई की वास्तविक वीडियो कवरेज जैसी दिखने वाली रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर कथित तौर पर डिजिटल छेड़छाड़ की



गई। इसमें भारत-चीन संबंधों, पाकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1 जैसे संवेदनशील विषयों पर नितिन नवीन के नाम से ऐसे बयान प्रसारित किए गए, जो भाजपा के अनुसार उन्होंने अपने वास्तविक संबोधन में नहीं दिए थे। पुलिस को शिकायत सौंपने के बाद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन तकनीक का दुरुपयोग कर किसी नेता के नाम से फर्जी भाषण तैयार करना और उसे वास्तविक बताकर प्रसारित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन डिजिटल जालसाजी और दुष्प्रचार का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत जांच और कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने, संबंधित सोशल मीडिया खातों की पहचान करने, उनके आईपी लॉग और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा मूल एएनआई वीडियो और कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो का साइबर फॉरेंसिक परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। इसके अलावा वीडियो तैयार करने और प्रसारित करने में शामिल लोगों की पहचान कर संबंधित सोशल मीडिया मंचों से विवादित सामग्री हटाने की कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नवाचार और जनकल्याण के लिए होना चाहिए, न कि फर्जी बयान तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि खराब करने और जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए। पार्टी ने मामले में शामिल लोगों और किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

सोने की चेन खींचने वाले फरार दो बदमाश राजस्थान से गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित नजफगढ़ में सड़क किनारे खड़ी महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हुए दो बदमाशों को द्वारका जिला पुलिस ने राजस्थान के खाटू श्याम जी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में एक के खिलाफ पहले से 66 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके साथी पर भी 16 आपराधिक मामलों में संलिप्तता रही है। पुलिस ने दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल टीवीएस एनटॉर्क स्कूटर और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपितों की पहचान 24 वर्षीय राजन सोनी उर्फ भोला और 22 वर्षीय हर्ष उर्फ अक्षय के रूप में हुई है। राजन विष्णु गार्डन, ख्याला का रहने वाला है जबकि हर्ष बेगम बाग, केशोपुर मंडी में रहता है। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि दो नवंबर को नजफगढ़ इलाके में एक महिला सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान टीवीएस एनटॉर्क स्कूटर पर सवार दो बदमाश आए और उसके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। इस मामले में नजफगढ़ थाने में प्राथमिकी के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी थी। जांच के दौरान 17 नवंबर को एंटी पीओ और जेल बेल सेल की टीम जय विहार इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि वारदात में शामिल दोनों आरोपित राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं। सूचना पर इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में टीम राजस्थान पहुंची। होटल में दो संदिग्ध मिले।

एक नजर

फरीदाबाद पुलिस का 13वां वीकेंड अभियान, तीन दिन में 152 गिरफ्तार

फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसने और जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष वीकेंड अभियान के माध्यम से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में 20 से 22 नवंबर तक चलाए गए तीन दिवसीय इस अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 152 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 587 ग्राम गांजा, 3.88 ग्राम एमडीएमए, 162 बोतल देसी व 63 बोतल अंग्रेजी शराब तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7010 रुपए बरामद किये हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों, अपराध शाखाओं और विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों, नशा तस्करों, अवैध शराब बेचने वालों तथा जुआ खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है, साथ ही 29 गुमशुदा व्यक्तियों को भी तलाश कर परिजनों से मिलाया है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए अवैध नशा में संलिप्त पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है तथा 587 ग्राम गांजा व 3.88 ग्राम एमडीएमए, बरामद किया है, वहीं नौ लोगों से 162 बोतल देसी शराब, 63 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। उन्होंने आगे बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 06 लोगों को गिरफ्तार कर 7010 रुपए बरामद किये हैं। उन्होंने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान उद्घोषित अपराधियों और जमानत पर फरार आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से कानून से बचकर घूम रहे 47 आरोपितों पर शिकंजा कसने में मदद मिली।

घर में घुसकर 20 से 25 राउंड फायरिंग, पिता-पुत्र समेत तीन घायल

पलवल। चांदहट गांव में घर में घुसकर मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थार गाड़ी में सवार होकर आए हमलावरों ने घर में घुसकर पहले मारपीट की और फिर राइफल, पिस्टल तथा देसी कट्टे से करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग में सुखबीर और उनके बेटे हरेंद्र के पैरों में गोली लग गई, जबकि सात वर्षीय हिमांशु ईंट-पत्थर लगने से घायल हो गया। तीनों घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांदहट थाना पुलिस के अनुसार गांव निवासी धर्मपाल उर्फ पाली ने शिकायत में बताया कि 22 नवंबर की देर शाम वह अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान शेखर, बिरम, सौरभ, जस्से और भोला थार गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी घर में घुस आए और धर्मपाल के साथ डंडों से मारपीट शुरू कर दी। शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने थार गाड़ी से राइफल, पिस्टल और देसी कट्टा निकाला और घर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाईं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग और झगड़े की आवाज सुनकर सुखबीर और उनका बेटा हरेंद्र घर से बाहर निकले। इसी दौरान दोनों के पैरों में गोली लग गई। वहीं, पास में मौजूद सात वर्षीय हिमांशु ईंट-पत्थर लगने से घायल हो गया। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने किया अवैध निर्माण ध्वस्त

नोएडा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। छपरौला में सहारा समतल के पास अवैध रूप से बनाए गए मकानों और प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। करीब तीन घंटे चली कार्रवाई में तीन एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया, जिसकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ रुपये है। नोएडा विकास प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों को शिकायत मिली थी कि अधिसूचित क्षेत्र में सहारा समतल के पास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। कालोनाइजर बिना अनुमति के कालोनी विकसित कर रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। ग्रेटर नोएडा के सीईओ डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग की टीम सोमवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और करीब तीन एकड़ जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि लगभग तीन घंटे की कार्रवाई में अवैध रूप से बने मकानों और प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तरों को ढहा दिया। इसके अतिरिक्त जमीन कब्जाने के लिए बनाई गई चारदीवारी को भी तोड़ दिया गया। ओएसडी ने बताया कि सहारा समतल क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में है। यहां पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण करने की छूट नहीं है। अनुमति के बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

गुरुग्रामः गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर फरीदाबाद की रैली ऐतिहासिक होगी- सर्वप्रिय त्यागी

गुरुग्राम,एजेंसी। भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 नवंबर को फरीदाबाद में आयोजित होने वाली भव्य रैली की तैयारियों, आगामी मन की बात कार्यक्रम तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का प्रेरणास्रोत है। उनकी 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को रैली में गुरुग्राम से अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने,



आह्वान किया कि वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ रैली की तैयारियों में जुटें तथा संत गुरु रविदास के संदेश को घर-घर तक पहुंचाएं। बैठक में आगामी रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर प्रभावी ढंग से आयोजित करने तथा अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी बूथ समितियों के लंबित संगठनात्मक कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

जिला मीडिया प्रभारी अजय दुआ ने बताया कि बैठक में जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, जिला महामंत्री अजीत यादव एवं मनीष सैदपुर, डिप्टी मेयर अनूप सिंह, ब्रह्म यादव सहित सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष तथा विभाग एवं प्रकोष्ठों के जिला संयोजक उपस्थित रहे। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर रैली को सफल बनाने तथा संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूरी जिम्मेदारी और सक्रियता से संपन्न करने का संकल्प लिया।

गुरुग्राम पुलिस ने 21 दिन में गिरफ्तार किए 81 साइबर ठग

गुरुग्राम। साइबर अपराधियों एवं ऑनलाइन ठगी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने 21 दिनों में 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध थाना टीमों द्वारा एक नवंबर 2026 से 21 नवंबर 2026 के दौरान साइबर अपराधियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की गई।

साइबर अपराध थाना की विभिन्न टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, गहन जांच एवं प्रभावी पुलिस कार्यवाही के माध्यम से साइबर ठगी में संलिप्त आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विभिन्न राज्यों में फैले साइबर अपराध एवं ठगी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आम नागरिकों को अपने जाल में फंसाने के लिए साइबर ठगी के अलग-अलग तरीके अपनाते थे। इनमें मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेडिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सोशल मीडिया एवं फेक इंस्टाग्राम आईडी फ्रॉड, एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी, ओएलएक्स एवं ऑनलाइन खरीद-बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी, इंस्टाग्राम हैकिंग, सेक्सटॉर्शन, टिकट बुकिंग फ्रॉड, फर्जी जॉब, ऑनलाइन रोजगार सहित अलग-अलग तरीकों से लोगों का विश्वास जीतकर उनकी मेहनत की कमाई ठगना शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले 15 सीपीयू, छह लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, एक मॉडम, एक राउटर, एक पेन ड्राइव व एक सिम बॉक्स इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामान बरामद किए गए हैं।

मकान का कब्जा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते अदालत का बेलिफ गिरफ्तार

पलवल। मकान का कब्जा दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय पलवल में तैनात बेलिफ श्याम सुंदर को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से मकान का कब्जा दिलाने की एवज में कुल 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसमें से वह पहले ही 20 हजार रुपये वसूल चुका था। सोमवार को शेष 50 हजार रुपये लेते हुए एसवी एंड एसीबी की टीम ने उसे आगरा चौक पर उसकी कार में दबोच लिया।

एसवी एंड एसीबी की फरीदाबाद इकाई के उपकेंद्र पलवल की टीम ने शिकायत मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 30, दिनांक 23 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने वर्ष 2019 में गांव रामपुर खोर निवासी हरिप्रमोद उर्फ प्रमोद दीक्षित से राधा कॉलोनी, आईटीआई के नजदीक पलवल में स्थित 287 वर्ग गज के दो मंजिला मकान को खरीदने के लिए समझौता किया था। बाद में मकान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके चलते मामला अदालत पहुंचा। अदालत के आदेश पर मकान की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के नाम कराई गई तथा उसे मकान का कब्जा दिलाने के आदेश भी जारी किए गए। मकान का कब्जा दिलाने के लिए अतिरिक्त सिविल जज की अदालत ने जिला न्यायालय पलवल में तैनात बेलिफ श्याम सुंदर को नियुक्त किया था। आरोप है कि बेलिफ ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर मकान का कब्जा दिलाने के बदले 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने आरोपी को पहले 20 हजार रुपये दे दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपी शेष 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर एसवी एंड एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में जाल बिछाया। सोमवार को आरोपी श्याम सुंदर शिकायतकर्ता से आगरा चौक पर अपनी कार में बैठकर 50 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। ट्रैप कार्रवाई का नेतृत्व एसवी एंड एसीबी यूनिट पलवल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार ने किया।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में ओएसडी स्तर के पांच अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) स्तर के पांच अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों का सोमवार को बंटवारा किया गया है। प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के बाद अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया जा रहा है। इससे एसीईओ स्तर के अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा पूर्व मे किया गया था। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ बलकार सिंह ने बताया कि ओएसडी अभिषेक पाठक पहले की तरह कार्मिक, वाणिज्यिक, खेल एवं ग्रेटर नोएडा के एनएमआरसी (नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य के अलावा भूलेख विभाग में वरिष्ठ प्रभार, जल, सीवर एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ प्रभार की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, ओएसडी गुंजा सिंह को सिस्टम, मार्केटिंग एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट कार्यालय में विभागाध्यक्ष के साथ भूलेख विभाग में वरिष्ठ प्रभार, एसेट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी, आवासीय संपत्ति, उद्योग एवं किसान आबादी विभाग के वर्क सर्किल-1 से 3 के कनिष्ठ प्रभार की



जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ओएसडी गिरीश कुमार झा संस्थागत में विभागाध्यक्ष के साथ भूलेख विभाग में वरिष्ठ प्रभार, अतिक्रमण हटाने, स्वास्थ्य व उद्यान विभाग में कनिष्ठ प्रभार, भूमि अधिग्रहण व विधानसभा प्रश्नों के नोडल अधिकारी रहेंगे। ओएसडी लवगीत कौर भूलेख व विधि में कनिष्ठ प्रभार के साथ किसान-आबादी के सर्किल-4 व 5 का कनिष्ठ प्रभार और अतिक्रमण हटाने का कार्य संभालेंगी। सीईओ के मुताबिक ओएसडी मुकेश कुमार सिंह शिक्षा समिति, वर्क सर्किल - ड्रेन, अर्बन सर्विसेज,गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय एवं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित कार्य, आईटी विभाग, किसान आबादी विभाग के वर्क सर्किल-6 से 8 में कनिष्ठ प्रभार, भूलेख व अतिक्रमण हटाने का कनिष्ठ प्रभार देखेंगे।

फरीदाबाद में पाकिस्तान व आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने का आरोप, व्यक्ति गिरफ्तार

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में पाकिस्तान और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', 'आईएसआई जिंदाबाद, अलकायदा जिंदाबाद और आतंकी हाफिज सईद जिंदाबाद' के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुन्नी खान के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह सेक्टर-3 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब के सामने की है। बताया जा रहा है कि वहां कुछ बुजुर्ग अपने काम से मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका सुन्नी खान से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान उसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद हिंदू जागरण मंच से जुड़े एक व्यक्ति ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में आरोपी कथित तौर पर नारे लगाता सुनाई दे



रहा है। वीडियो में वह अपना वीडियो बनाने की चुनौती देते हुए भी दिखाई देता है। मामले की शिकायत सीनियर सिटीजन क्लब के महासचिव चरण सिंह ने सेक्टर-3 पुलिस चौकी में दी। शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और काफी समय से बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में रह रहा था। उसके धर्म परिवर्तन किए जाने की बात भी सामने आई है, हालांकि इस संबंध में पुलिस की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि विवाद के दौरान नारे लगाने के पीछे क्या कारण थे और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलू क्या हैं।

नूंह में अवैध खनन के लगे दो ट्रैक्टर बरामद

नूंह। नूंह जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नूंह पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी मिली है। एंटी व्हीकल थेफ्ट (एवीटी) और माइनिंग स्टाफ की संयुक्त टीम ने रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान अवैध खनन में संलिप्त दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर संबंधित थानों में खड़ा करा दिया है।

मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। नूंह पुलिस के अनुसार रविवार 22 नवंबर की रात को एवीटी और माइनिंग स्टाफ की टीम ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान थाना सदर तावडू क्षेत्र के गांव चीला में एक ट्रैक्टर अवैध खनन में संलिप्त पाया गया। टीम ने मौके पर ही ट्रैक्टर को जब्त कर थाना सदर तावडू में जमा करा दिया। इसी अभियान के तहत थाना पिनगवां क्षेत्र के गांव शाह चोखा में भी अवैध खनन में संलिप्त एक अन्य ट्रैक्टर पकड़ा गया। उसे जब्त कर थाना पिनगवां में खड़ा कराया गया है।

गुरुग्राम के सभी सार्वजनिक स्थल और पार्क घोषित हुए नो स्मोकिंग जोन

गुरुग्राम। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और तंबाकू के धुएं से मुक्त बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक स्थलों और पार्कों को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया गया है। है। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने इसके आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक स्थलों को नो स्मोकिंग जोन घोषित करते हुए धूम्रपान, तंबाकू सेवन और सिगरेट एवं बीड़ी के टुकड़े इधर-उधर फेंकने पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। जारी आदेश में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बाजार, बस स्टॉप, बस स्टैंड और सार्वजनिक परिवहन के साधन, सभी पार्क, ग्रीन बेल्ट, खेल के मैदान और खुले सार्वजनिक स्थान, जिनका स्वामित्व, रखरखाव या प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया जाता है। इनमें शेड, गजिबो और अन्य कवर किए गए ढांचे भी शामिल हैं, सभी कार्यालय, सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, पार्किंग स्थल और सार्वजनिक शौचालय परिसर आदि नो स्मोकिंग जोन में शामिल हैं। आदेश के अनुसार, इन स्थानों पर कोई भी व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, सिगार या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही सिगरेट एवं बीड़ी के टुकड़े फेंकने और तंबाकू खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नो स्मोकिंग जोन में धूम्रपान करने वालों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 21 के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सिगरेट एवं बीड़ी के टुकड़े इधर-उधर फेंकने तथा तंबाकू खाकर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रतिष्ठान द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फरीदाबाद में साइबर ठगी के तीन आरोपी गिरफ्तार, लाखों की धोखाधड़ी का खुलासा

फरीदाबाद। साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति को टेलीग्राम टास्क के नाम पर सात लाख 65 हजार 839 रुपये का चूना लगाया, जबकि दूसरे मामले में फोन हैक कर एक व्यक्ति के बैंक खाते से दो लाख 27 हजार 87 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल नौ लाख 92 हजार 926 रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है।

पहले मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने पर्वतीय कॉलोनी निवासी व्यक्ति से टेलीग्राम टास्क के नाम पर ठगी करने के मामले में दिल्ली निवासी खाताधारक सुरेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 27 अक्टूबर 2026 को उसके पास एक युवती का फोन आया। उसने पार्ट टाइम जॉब का झांसा दिया और व्हाट्सएप पर एक टेलीग्राम आईडी भेजी। आईडी ज्वाइन करने के बाद पीड़ित को प्रीपेड टास्क दिए जाने लगे। अधिक मुनाफे का लालच देकर उससे अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल सात लाख 65 हजार 839 रुपये निवेश करवा लिए गए। इसके बाद न तो उसे कोई मुनाफा मिला और न ही उसकी रकम वापस की गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वह इस ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते का खाताधारक है। उसके खाते में ठगी की रकम में से 50 हजार रुपये आए थे। आरोप है कि उसने अपना बैंक खाता आगे साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। आरोपी बीकॉम पास है और प्राइवेट नौकरी करता है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। दूसरे मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने तिगांव निवासी व्यक्ति के साथ फोन हैक कर दो लाख 27 हजार 87 रुपये की ठगी करने के मामले में दो आरोपियों सलमान और अरबाज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 18 जुलाई 2026 को उसका मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया और अपने आप चलने लगा।

पोस्टमार्टम में खुलासा, जिंदा महिला को पत्थर बांधकर नाले में फेंका, डूबने से हुई मौत

फरीदाबाद। समयपुर नाले में पत्थर से बांधकर फेंकी गई महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अहम सुराग मिला है। डायटम टेस्ट में महिला के फेफड़ों में पानी के अंश पाए गए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि नाले में फेंके जाने के दौरान महिला जिंदा थी और उसकी मौत डूबने से हुई। हालांकि, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि उसे पहले बेहोश या बेसुध तो नहीं किया गया था।

14 नवंबर को समयपुर नाले में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्यारोपियों ने शव को चुन्नी और चादर जैसे कपड़ों से करीब 15 से 20 किलो के पत्थर के साथ बांध रखा था, ताकि शव पानी में ऊपर न आ सके। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पत्थर बांधने के पीछे शव को छिपाने और उसकी पहचान मिटाने की कोशिश तो नहीं थी। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। उसके शरीर पर मंगलसूत्र और शादी से जुड़े अन्य आभूषण मिले थे। शव लंबे समय तक पानी में रहने के कारण काफी गल चुका था। इस वजह से चेहरा और शारीरिक पहचान के दूसरे संकेत स्पष्ट नहीं हो पाए। घटनास्थल से भी कोई पहचान पत्र या



दस्तावेज नहीं मिला, जिससे पुलिस को महिला के नाम और पते का सुराग मिल सके। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच और सीन ऑफ क्राइम की टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटा चुकी हैं। फिलहाल जांच में सबसे बड़ी अड़चन मृतका की पहचान है। पुलिस आसपास के जिलों में महिलाओं की गुमशुदगी की शिकायतों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। पहचान सामने आने के बाद ही यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि महिला कहां रहती थी, किन लोगों के संपर्क में थी और आखिरी बार उसे किसके साथ देखा गया था।

बड़ा फैसला-बड़ा मायने

अभिषेक शुक्ल

वर्ष 1965 में वेल्डर के रूप में सरकारी सेवा शुरू करने वाले प्रेम सिंह को नियमित होने के लिए 37 साल इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन 2007 में सेवानिवृत्ति के बाद यह कहकर उनकी पेंशन रोक दी गई कि कार्य-प्रभारित (वर्क-चार्ज्ड) सेवा की गिनती नहीं होगी। 2019 में देश के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने इस अन्याय को खत्म किया, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसले को बेअसर करने के लिए 2021 और 2025 में पूर्वव्यापी कानून बना डाले। आखिरकार, 18 नवंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट कर दिया कि नियमितीकरण के बाद कर्मचारी की शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का 'जन्मचिह्न' हमेशा के लिए मिट जाता है। उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त दो वैधीकरण कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल लाखों कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों को नया जीवन दिया है, बल्कि विधायिका की सीमाओं और कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकताओं को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। दशकों तक सरकारी विभागों में कार्य-प्रभारित (वर्क-चार्ज्ड), दैनिक वेतनभोगी, मस्टर-रोल या अस्थायी कर्मचारी के रूप में पसीना बहाने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर तकनीकी नियमों की आड़ में खाली हाथ लौटा दिया जाता था। लेकिन 18 नवंबर, 2026 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने इस प्रशासनिक प्रवृत्ति पर निर्णायक प्रहार किया है।

उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नॉन-गजेटेड एम्प्लॉई एसोसिएशन बनाम मुख्य सचिव एवं अन्य (2026 इ्रहस्ष्ट 1252) मामले में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2021 और 2025 के दोनों पेंशन वैधीकरण अधिनियमों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले को हाल के वर्षों के अन्य प्रमुख निर्णयों के साथ जोड़कर देखें, तो देश के सेवा और पेंशन कानून में चार बड़े संवैधानिक बदलाव साफ तौर पर उभरते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फैसले में है। तब तीन जजों की पीठ ने यूपी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को सीमित रूप में पढ़ते हुए और सिविल सेवा विनियमन के विनियम 370 को रद्द करते हुए स्पष्ट किया था कि नियमित होने के बाद कर्मचारियों की पूर्ववर्ती वर्क-चार्ज्ड सेवा को पेंशन के लिए 'अर्हकारी सेवा' में गिना जाएगा। पुनर्विचार याचिका खारिज होने और क्यूरेटिव याचिका वापस लेने के बाद राज्य सरकार ने अदालती आदेश के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए विधायी रास्ता चुना। पहले 2020 में अध्यादेश और 2021 में अधिनियम लाकर 'अर्हकारी सेवा' की नई परिभाषा गढ़ी गई, और फिर 2025 में एक नया कानून लाकर 'मौलिक नियुक्त व्यक्ति' की शर्त जोड़ दी गई। दोनों कानूनों को 1 अप्रैल, 1961 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस विधायी कवायद पर बेहद सख्त टिप्पणी की। स्वामी विवेकानंद के कथन को उद्धृत करते हुए अदालत ने कहा कि यहां केवल बोतल बदली गई है, लेकिन उसके भीतर की पुरानी समस्या जस की तस है। पृथ्वी कॉटन मिल्स, इंडियन एल्युमिनियम और मदन मोहन पाठक जैसे प्रमुख निर्णयों के आलोक में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायिका किसी फैसले के कानूनी आधार या दोष को दूर करने के लिए कानून बदल सकती है, लेकिन वह केवल शब्दों का हेरफेर कर एक अंतिम न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अदालत ने संविधान सभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर की उस चेतावनी को भी याद दिलाया कि संविधान का स्वरूप बदले बिना भी प्रशासनिक तरीकों में बदलाव करके उसकी आत्मा को विकृत किया जा सकता है।

सेवा विधि के क्षेत्र में इस फैसले का सबसे बड़ा सैद्धांतिक योगदान 'जन्मचिह्न के विलोपन' के सिद्धांत का विस्तार है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शैलेंद्र सिंह बनाम भारत संघ (2024) और इन री: हाईकोर्ट जजेस पेंशन रिफिक्सेशन (2025) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि एक बार जिला न्यायपालिका या बार से उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद नियुक्ति का स्रोत (जन्मचिह्न) मिट जाता है और सेवानिवृत्ति लाभों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी संवैधानिक दर्शन को आम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है। अदालत ने दो टूक कहा कि जब किसी एड-हॉक, दैनिक वेतनभोगी, मस्टर-रोल या वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी को किसी विधिवत योजना के तहत नियमित कर दिया जाता है, तो वह नियमित सेवा की मुख्यधारा का हिस्सा बन जाता है। नियमितीकरण के साथ ही उसकी शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का 'जन्मचिह्न' हमेशा के लिए मिट जाता है। सरकार पूर्वव्यापी कानून बनाकर उस मिटे हुए अंतर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 16 (अवसर की समानता) और 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का सीधा उल्लंघन है। यह रुझान हाल के अन्य फैसलों में भी दिखता है। जग्गो बनाम भारत संघ (2024) में अदालत ने उमादेवी (2006) फैसले के चुनिंदा दुरुपयोग के प्रति आगाह करते हुए कहा था कि लंबे समय से जरूरी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के हक सिर्फ पदनाम के आधार पर नहीं मारे जा सकते। इसी तरह, जून 2026 के भिखानी देवी बनाम भारत संघ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि संविधान के तहत अर्जित अधिकार है और दशकों तक अस्थायी दर्जे पर काम करने वाले कर्मियों को औपचारिक नियमितीकरण के अभाव में इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

अकसर सरकारें कर्मचारियों के देयकों के मामले में सरकारी खजाने पर भारी बोझ की दलील देती हैं। इस मामले में भी राज्य की ओर से हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय भार की आशंका जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए न्यायिक संज्ञान लिया कि हाल के समय में राज्य ने पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि सौंदर्यकरण जैसे विवेकाधीन खर्चों को नागरिकों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। वित्तीय सीमाएं भुगतान के तरीके को तय कर सकती हैं, लेकिन वे कानूनी दायित्व से बचने का बहाना नहीं बन सकतीं। पेंशन न्यायशास्त्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास बकाया राशि (एरियर) की समय-सीमा को



लेकर हुआ है। सामान्य नियम के तहत, जैसा कि शिव दास, तरसेम सिंह और प्रेम सिंह में तय किया गया था, देरी से अदालत आने पर पेंशन का मौद्रिक बकाया याचिका दायर करने से पूर्व के तीन वर्षों तक सीमित रहता है। 18 नवंबर, 2026 के फैसले में अदालत ने इस नियम को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही एक मानवीय संतुलन भी साधा। अदालत ने स्पष्ट किया कि तीन वर्ष की यह सीमा उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होगी, जिनका निधन प्रेम सिंह का फैसला आने से पहले ही हो चुका था। इसके अलावा, इसी वर्ष आए माया बनर्जी बनाम भारत संघ (2026) और पुराने एस.के. मस्तान बी फैसले को भी कोर्ट ने अनुच्छेद 15(3) के आलोक में स्पष्ट करते हुए बताया कि असहाय विधवाओं के पारिवारिक पेंशन के मामलों में तीन साल की सीमा की कठोरता लागू नहीं होती। उच्चतम न्यायालय ने अपने ताजा फैसले को 'इन रेम' (सर्वव्यापी) घोषित किया है। इसका अर्थ है कि इसका लाभ केवल मुकदमा लड़ने वाले कर्मचारियों या संघों के सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर उस पात्र कर्मचारी को मिलेगा जो इस दायरे में आता है। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अब अपने सेवा विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं, जिसका निस्तारण छह महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई दावा अस्वीकार करना हो, तो कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना और तर्कसंगत आदेश पारित किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकेगा। भुगतान में छह महीने से अधिक की देरी होने पर राज्य को 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। साथ ही, अवमानना याचिकाओं में अंतिम छह महीने की मोहलत देते हुए अदालत ने चेतावनी दी है कि अब चूक होने पर इसे 'गंभीर अवमानना' माना जाएगा। भविष्य की मुकदमेबाजी को पारदर्शी बनाने के लिए अदालत ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश भी दिया है कि अब जब भी कोई कर्मचारी संगठन अपने सदस्यों के लिए रिट याचिका दायर करे, तो याचिका के साथ उस तिथि तक के सभी सदस्यों की पूरी सूची भी संलग्न करे।

जब सरकारी कामकाज का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और अस्थायी व संविदा नियुक्तियों का दायरा बढ़ रहा है, तब 18 नवंबर, 2026 का यह फैसला महज अतीत के अन्याय का सुधार नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक संवैधानिक दिशा-निर्देश है। 'जन्मचिह्न के विलोपन' का जो सिद्धांत नियमित हो चुके कर्मचारियों के लिए ढाल बना है, वह आने वाले समय में देश भर की सेवा नीतियों की कसौटी तय करेगा कि एक बार व्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने के बाद किसी नागरिक के साथ उसकी शुरुआती नियुक्ति के दर्जे के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। विधायिका और कार्यपालिका के लिए भी यह भविष्य का स्पष्ट मानक है कि शब्दों के हेरफेर से न तो अंतिम न्यायिक आदेशों को बेअसर किया जा सकेगा और न ही वित्तीय बोझ की दलील देकर संवैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ा जा सकेगा। इक्कीसवीं सदी के कल्याणकारी राज्य की असली परीक्षा केवल भव्य परियोजनाओं और सौंदर्यकरण में नहीं, बल्कि इस बात में होगी कि वह अपने उन नागरिकों के बुढ़ापे को कितनी गरिमा और सुरक्षा दे पाता है, जिन्होंने उसकी नींव रखने में अपना पूरा जीवन खपा दिया।

गुरूनानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व (गुरुनानक जयंती) 24 नवंबर को मनाया जाएगा। यह उनकी 557वीं जयंती होगी। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुनानक देवजी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब (पंजाब, पाकिस्तान) के नाम से जाना जाता है। लाहौर के पास स्थित (वर्तमान पाकिस्तान में) है। वह स्थान सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु हैं। वे सत्य, करूणा, समानता और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू (कालूराम) था। उन्होंने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। गुरु नानक देव जी की शिक्षा- एक ईश्वर की उपासना, समानता, ईमानदार जीवन और निस्वार्थ सेवा पर आधारित थीं। उन्होंने समाज में एकता, सच्चाई और मानवता का संदेश दिया। वे कहते थे कि एक ओंकार (ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है और सभी का सृष्टिकर्ता है। नाम जपो:- हमेशा ईश्वर का स्मरण और भजन करना चाहिए। किरत करो:- मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमाना चाहिए।

(गुरुनानक जयंती /24 नवंबर/विशेष) संदेशों में निहित है देश की प्रगति

डॉ.लोकेश कुमार चन्देल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहा करते हैं कि गुरुनानक देव जी का जीवन, संदेश और शिक्षाएं मानवता तथा देश की प्रगति के लिए प्रेरणादायक हैं। गुरु नानकजी ने जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनके मंत्र 'नाम जपो, किरत करो, वंड छको' का आध्यात्मिक चिंतन, कर्तव्यनिष्ठा से मेहनत, भौतिक समृद्धि और आपस में मिल-बांटकर खाने और सामाजिक समरसता की प्रेरणा देने वाला बताया। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि गुरु नानकजी का जीवन और संदेश शाश्वत ज्ञान से मानवता का मार्गदर्शन करता है और उनकी करुणा, समानता, विनम्रता व सेवा की शिक्षा समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

गुरूनानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व (गुरुनानक जयंती) 24 नवंबर को मनाया जाएगा। यह उनकी 557वीं जयंती होगी। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुनानक देवजी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब (पंजाब, पाकिस्तान) के नाम से जाना जाता है। लाहौर के पास स्थित (वर्तमान पाकिस्तान में) है। वह स्थान सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु हैं। वे सत्य, करूणा, समानता और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालू (कालूराम) था। उन्होंने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। गुरु नानक देव जी की शिक्षा- एक ईश्वर की उपासना, समानता, ईमानदार जीवन और निस्वार्थ सेवा पर आधारित थीं। उन्होंने समाज में एकता, सच्चाई और मानवता का संदेश दिया। वे कहते थे कि एक ओंकार (ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है और सभी का सृष्टिकर्ता है। नाम जपो:- हमेशा ईश्वर का स्मरण और भजन करना चाहिए। किरत करो:- मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमाना चाहिए। वंड छको:- अपनी कमाई और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ मिल-बांटकर साझा करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से मानव समानता, निस्वार्थ सेवा, परिश्रम और सांप्रदायिक सद्भाव पर आधारित हैं। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उन्नति केवल संन्यास लेने से नहीं, बल्कि समाज में रहते हुए नैतिक और न्यायपूर्ण जीवन जीने से होती है।

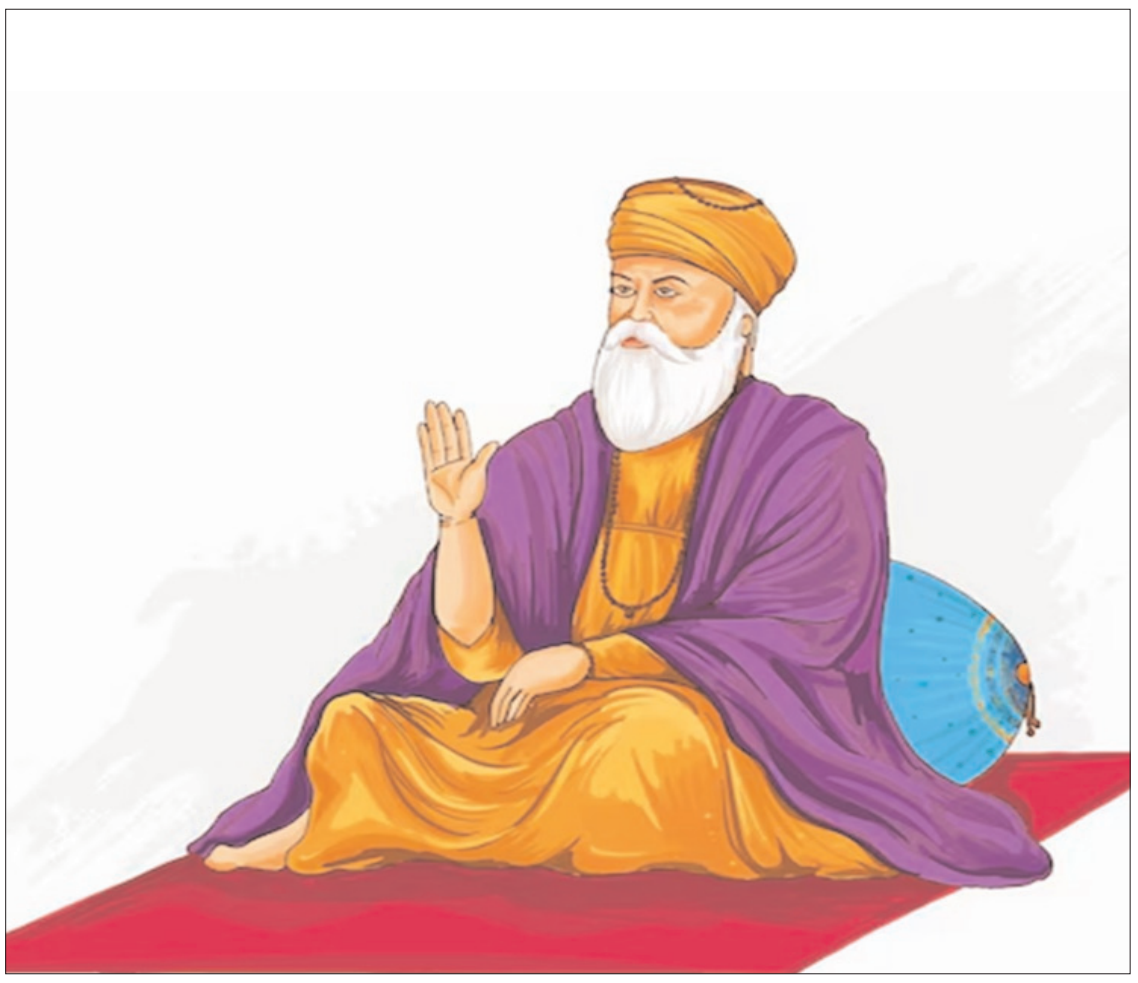

सामाजिक समानता और जाति प्रथा का विरोध:-गुरु नानक देवजी ने जन्म या जाति के आधार पर होने वाले ऊंच-नीच के भेदभाव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने समझाया कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। समाज से छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने 'संगत' (एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन करना) और 'पंगत' या लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर में राजा हो या रंक, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, सभी को एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करना अनिवार्य था। मध्यकालीन समाज में जब महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, छोटी-छोटी बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। डर के कारण जन्म के साथ ही बच्चियों को मार दिया जाता था। ऐसी स्थिति में गुरु नानकजी ने स्त्री-पुरुष की बराबरी की पुरजोर वकालत की। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में कहा कि 'सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान' (उस स्त्री को बुरा क्यों कहा जाए, जो राजाओं और महान पुरुषों को जन्म देती है)। उन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का भी जमकर विरोध किया। ईमानदारी की कमाई और साझा करना (किरत करो और वंड छको) किरत करो (ईमानदारी से परिश्रम)- मनुष्य को किसी का शोषण किए बिना, अपनी मेहनत और ईमानदारी से आजीविका कमानी चाहिए। उन्होंने अमीर जमींदार मलिक भागो के शाही भोजन को ठुकराकर एक गरीब बढ़ई भाई लालो की रूखी-सूखी रोटी को स्वीकार किया, क्योंकि भाई लालो की कमाई मेहनत की थी।

वंड छको (मिल-बांटकर खाना) : अपनी ईमानदारी की कमाई का एक हिस्सा गरीबों, जरूरतमंदों और समाज की भलाई के लिए साझा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इससे समाज में आर्थिक विषमता कम होती है और परोपकार की भावना बढ़ती है।

धार्मिक सद्भाव और मानवतावाद:- उन्होंने 'इक ओंकार' का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है और वह हर प्राणी में निवास करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला वाक्य था 'न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान'। उनका आशय था कि ईश्वर की नजर में सभी इंसान केवल 'मानव' हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच की कट्टरता को कम कर आपसी भाईचारे और शांति का संदेश दिया। अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों का खंडन:- उन्होंने समाज में फैले पाखंड, मूर्ति पूजा और निरर्थक कर्मकांडों का विरोध किया। हरिद्वार में जब लोग पूर्व दिशा की ओर सूर्य और अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर जल फेंकना शुरू कर दिया। पूछने पर उन्होंने तर्क दिया कि यदि उनका जल लाखों मील दूर पूर्वजों तक पहुंच सकता है, तो मेरा जल कुछ मील दूर करतारपुर के खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? इस प्रकार उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से निकालकर कर्म प्रधान बनने की प्रेरणा दी। वे कहते थे कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। बिना किसी स्वार्थ या बदले की भावना के दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अहंकार को मनुष्य और समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताया और विनम्रता, क्षमा तथा करुणा को अपनाने की शिक्षा दी। बहरहाल, हम यही कह सकते हैं कि उनके सिद्धांत आज विश्व में फैल रहे वैमनस्यता समाप्त करने का मुख्य जरिया हो सकता है। नानक देव जी ने समानता, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज को जोड़ने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए सभी को एक समान माना। उन्होंने लंगर की शुरुआत की, जहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उन्होंने ऊंच-नीच और जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया और सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान बताया।

विचार

वैश्विक बाजार में भारतः निर्यात के नए भूगोल से बदल रही आर्थिक तस्वीर

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

विश्व में बदलते व्यापारिक समीकरणों और बाजारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत का वस्तु निर्यात नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में अफ्रीका से लेकर एशिया, अमेरिका और यूरोप तक भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होना इस बदलाव का संकेत है। खास बात यह है कि भारत के निर्यात की रफ्तार आज पारंपरिक बाजारों से आगे जाकर अफ्रीका में 44 प्रतिशत, एशिया में 21 प्रतिशत और अमेरिका में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करा रही है। देखने में आ रहा है कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, रसायन और औषधि उद्योग इस विस्तार के प्रमुख आधार बनकर उभरे हैं। हमारे लिए निर्यात बढ़ने का अर्थ है कि दुनिया के दूसरे देशों में उस देश के उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। एशिया को भारत का निर्यात 21 प्रतिशत बढ़कर 103.84 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका को 66.82 अरब डॉलर और यूरोप को 51.04 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन अफ्रीका का रहा, जहां भारतीय वस्तुओं का निर्यात 44 प्रतिशत बढ़कर 31.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत का निर्यात आज कुछ गिने-चुने देशों और बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह विविधीकरण आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, मिस्र, नाइजीरिया और मोजाम्बिक जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। तंजानिया को निर्यात में 121 प्रतिशत और केन्या में 101 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मिस्र में यह वृद्धि 73 प्रतिशत रही। दक्षिण अफ्रीका को 5.69 अरब डॉलर का निर्यात हुआ।

इस विस्तार के पीछे पेट्रोलियम उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी दिखाई देती है। अफ्रीका को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 137 प्रतिशत बढ़कर 11.85 अरब डॉलर पहुंच गया। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात भी 29 प्रतिशत बढ़कर 7.48 अरब डॉलर हो गया। वैश्विक विकास के नजरिए से देखें तो अफ्रीका तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं, आधारभूत संरचना की जरूरतों और बढ़ते उपभोक्ता बाजार वाला महाद्वीप है। ऐसे में स्वभाविक है कि भारत के लिए भी यहां व्यापार विस्तार के साथ औद्योगिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों की भी व्यापक संभावनाएं हैं।यहां एक नजर एशिया पर भी डाल लेते हैं, यह लंबे समय से भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। अब इस बाजार में भारतीय निर्यात की बढ़ती गति नए अवसर पैदा कर रही है। चीन को निर्यात 36 प्रतिशत बढ़कर 11.39 अरब डॉलर और सिंगापुर को निर्यात 103 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11.07 अरब डॉलर पहुंचा है। मलेशिया में 83 प्रतिशत और हांगकांग में 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। बांग्लादेश, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे बाजार भी भारत के निर्यात विस्तार में योगदान दे रहे हैं। इन राष्ट्रों में उत्पादों की बात करें तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 27.47 अरब डॉलर रहा। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 17.05 अरब डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 10.54 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 91 प्रतिशत की वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में एशिया में 91 प्रतिशत की वृद्धि इस क्षेत्र की संभावनाओं को रेखांकित करती है। इंजीनियरिंग उत्पादों की व्यापक मांग भी भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। अफ्रीका एवं एशिया की तरह ही अमेरिका भारत के निर्यात का एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। इस क्षेत्र में निर्यात 13 प्रतिशत बढ़कर 66.82 अरब डॉलर हो गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जहां 50.80 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया। ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा में भी भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 19.19 अरब डॉलर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का 15.35 अरब डॉलर रहा। औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात भी 6.59 अरब डॉलर तक पहुंचा। यूरोप में भारत का निर्यात 8 प्रतिशत बढ़कर 51.04 अरब डॉलर हो गया। ब्रिटेन और जर्मनी प्रमुख बाजार रहे। स्पेन को निर्यात में 45 प्रतिशत, इटली में 25 प्रतिशत और तुर्किये में 72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वस्तुतः इन सभी आंकड़ों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और प्रतिस्पर्धी कीमतों की कसौटी अपेक्षाकृत कठिन होती है। ऐसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच घरेलू उद्योगों की क्षमता के विस्तार का संकेत देती है।

एक नजर

जन्मभूमि बुढैला पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत



बक्सर/नवानगर। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जितेंद्र सिंह के अपने पैतृक गांव बुढैला पहुंचने पर ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बक्सर जिले के नवानगर थाना क्षेत्र स्थित उनकी जन्मभूमि बुढैला में ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव और उल्लास का माहौल रहा। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सारंगी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव से निकलकर आए युवा को प्रदेश स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान देने के लिए वे हृदय से धन्यवाद देते हैं। यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं का है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग संगठन के साथ मजबूती से खड़ा है। युवाओं के विश्वास और समर्थन के बल पर भाजपा युवा मोर्चा को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता मनोज सिंह, राजू सिंह, जिला प्रवक्ता विमलेश सिंह, अभय सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भोला सिंह, विनोद चौबे सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। अपनी जन्मभूमि पर मिले इस भव्य सम्मान से जितेंद्र सिंह काफी उत्साहित नजर आए।

सुशासन दिवस पर डीएमसीएच ऑडिटोरियम में होगा 'नीतीश संवाद'



दरभंगा। सुशासन दिवस के अवसर पर डीएमसीएच ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले 'नीतीश संवाद' कार्यक्रम की सफलता को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसकी जानकारी जदयू जिलाध्यक्ष सह विधायक राजेश कुमार उर्फ ईश्वर मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सहित जिले के जनप्रतिनिधि, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से सरकार की विकास यात्रा और उपलब्धियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमलोगों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगातार बैठकें आयोजित कर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है।

सहयोग पोर्टल के आवेदनों का समय पर निष्पादन करें अधिकारी : डीएम

सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निष्पादन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से निपटारा किया जाए। डीएम ने सर्वे कर राशन कार्ड, श्रम कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित मामलों की पहचान कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जन संवाद, राशन कार्ड, एनीमिया अभियान और पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

बैंकिंग की सुरक्षित नौकरी छोड़ शुरू किया सीमेंट का कारोबार, अब हर महीने हो रही 80 हजार की बचत

भागलपुर। बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षित नौकरी छोड़कर स्वरोजगार का जोखिम उठाने वाले राजीव आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। राजीव प्रदीप पहले बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत थे। नौकरी के दौरान उन्हें हर महीने महज 15 से 20 हजार रुपये की ही बचत हो पाती थी, जिससे वे संतुष्ट नहीं थे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और कुछ बड़ा करने की चाह में उन्होंने नौकरी छोड़ खुद का व्यवसाय शुरू करने का साहसिक फैसला लिया। राजीव ने भागलपुर में पेवर ब्लॉक, सीमेंटेड ईंट, गमले और पार्कों में लगने वाली सीमेंटेड बेंच जैसे उत्पाद बनाने का काम शुरू किया। नए बाजार में पैर जमाना उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआती दौर में कई चुनौतियां सामने आईं और कई बार उन्हें अपनी जमा पूंजी डूबने का डर भी सताने लगा। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और गुणवत्ता व मेहनत के बल पर बाजार में अपनी पहचान बनाई। धीरे-धीरे उनके उत्पादों की मांग बढ़ी और कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। आज राजीव अपने व्यवसाय से हर महीने करीब 80 हजार रुपये की शुद्ध बचत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने काम के जरिए कई अन्य फैक्ट्रियों को भी सहयोग दे रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों के कारोबार को भी आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। राजीव की यह सफलता आज उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू कर रोजगार सृजन करना चाहते हैं।

बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अख्तरुल ईमान सार्वजनिक माफी मांगें : सैफ अली खान

अररिया। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान द्वारा शादी-विवाह और दुल्हनों को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। अररिया जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सैफ अली खान ने विधायक के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ बताया है। उन्होंने अख्तरुल ईमान से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। सैफ अली खान ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों, फिजूलखर्ची और गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाना हर जिम्मेदार व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन समाज सुधार के नाम पर बहू-बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। एक जनप्रतिनिधि और समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी भाषा और व्यवहार की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस्लाम महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने की शिक्षा देता है। कुरान और हदीस में जुबान की हिफाजत, दूसरों की इज्जत और अच्छे अखलाक पर विशेष जोर दिया गया है। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद ने भी महिलाओं के साथ बेहतरीन व्यवहार करने की शिक्षा दी है। ऐसे में महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विपरीत है। खान ने कहा कि अगर शादी-विवाह में फिजूलखर्ची या कोई सामाजिक बुराई है तो उसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। लोगों को समझाया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों से



ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे समाज की बेटियों को अपमानित महसूस हो। सैफ अली खान ने आगे कहा कि सीमांचल की जनता ने जनप्रतिनिधियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास और सामाजिक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए चुना है। इसलिए नेताओं को ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए, न कि ऐसे बयान देने चाहिए जिनसे सामाजिक मर्यादा और महिलाओं के सम्मान पर सवाल खड़े हों। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इस तरह की अमर्यादित भाषा का विरोध करता है और अख्तरुल ईमान से मांग करता है कि वे अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

कर्मचारी महासंघ सुपौल की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव, डॉ. अमन कुमार बने अध्यक्ष

सुपौल। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा सुपौल की नई जिला कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। पांचवें जिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शरद कुमार, प्रदेश महामंत्री सुबेश सिंह तथा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा होते ही सम्मेलन में मौजूद सैकड़ों कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया और बधाई दी।

नई कार्यकारिणी में डॉ. अमन कुमार को जिला अध्यक्ष तथा सूर्य नारायण राम, सहायक प्रशासी पदाधिकारी, सुपौल अनुमंडल को जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं विभूति कुमार को मानद सदस्य, सीडी सिंह को मुख्य संरक्षक तथा मनोज कुमार को सम्मानित अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ. गौतम कुमार, विजय कुमार, अशोक कुमार, वीरेंद्र कुमार, संजय कुमार राम, कुशेश्वर कुमार, पंकज कुमार, सचिन कुमार सिंह, श्यामदेव सादा, दिग्विजय पाठक, रमण कुमार, खेलानंद कुमार, मणिकांत कामत, पंकज कुमार वर्मा, नवनीत प्रसाद ज्वाला और जयमद झा को चयनित किया गया। सहायक जिला मंत्री पद पर राजकिशोर रंजन, मोहम्मद अफरोज आलम, अमित कुमार राजा, राजेश कुमार, मनीष कुमार राउत, मनीष कुमार मुस्कान, चंदन कुमार, मनोज कुमार पाल, राधेश्याम कुमार, अश्वनी कुमार सिन्हा, राजा मिश्रा, मुकेश कुमार कामत, अजय कुमार मल्लिक और सूर्य नारायण मंडल को जिम्मेदारी दी गई।

संयुक्त मंत्री के रूप में श्रवण कुमार, अमरेश कुमार चौधरी और अमित कुमार पासवान को नामित किया गया। कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश, उप कोषाध्यक्ष मोहम्मद रहमत तथा कार्यालय मंत्री मोहम्मद रहमान और प्रवीण कुमार सिंह को मनोनीत किया गया। महिला उप समिति में इंदु कुमारी, रूबी कुमारी, रेणु कुमारी, कुमारी आभा और सपना रानी को शामिल किया गया। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मोहम्मद शमशेर आलम और विकास कुमार को दी गई। अनुमंडल मंत्री के रूप में सिकेन्द्र कुमार को त्रिवेणीगंज, नारायण पासवान को वीरपुर, भीष्म कुमार को निर्मली तथा मिथलेश सिंह को सुपौल की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बिहार और बक्सर के विकास को मिली नई गति, प्रधानमंत्री ने दी 34 हजार करोड़ की 227 परियोजनाओं की सौगात

बक्सर,एजेंसी। बिहार के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैशाली की ऐतिहासिक धरती से बिहार को करीब 34 हजार करोड़ रुपये की 227 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें कच्ची दरगाह से बिदुपुर को जोड़ने वाले छह लेन के गंगा पुल को 'नीतीश सेतु' नाम देने के साथ बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई समेत बिजली, शिक्षा, पशुपालन और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये बातें भाजपा के बक्सर विधायक आनंद मिश्रा एवं जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश भुवन ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहीं।

दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और बिहार सरकार के समन्वित प्रयासों से राज्य विकास, ऊर्जा, शिक्षा, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। यह डबल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बक्सर के चौसा स्थित ताप विद्युत परियोजना की 600 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित किया जाना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। 7,037 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की दोनों इकाइयों के संचालन से कुल 1,320 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी। इससे बिजली आपूर्ति के साथ औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। नेताओं ने बताया कि छोटका सिंहपुरा में 12.66 करोड़ रुपये की लागत से 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहां 10-10 एमवीए क्षमता के दो ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। इससे 56 गांवों के लगभग 11,500 परिवारों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए नावानगर में 125 एकड़ भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की योजना को भी महत्वपूर्ण बताया। वहीं, नावानगर के परसागंडा, इटाढ़ी के बड़का गांव और सिमरी के ठकाईच में विद्यालय भवनों के निर्माण एवं उद्घाटन से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन योजनाओं पर 9.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डुमरांव के गोकुल ग्राम में 37.43 करोड़ रुपये की लागत से हीफर पालन केंद्र की स्थापना को पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम पहल बताया गया।

24 नवंबर को पूरे बिहार में मनेगा 'नीतीश संवाद एवं सुशासन दिवस', जनता के बीच विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखेंगे जदयू कार्यकर्ता

सुपौल,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की ऐतिहासिक तिथि 24 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) पूरे प्रदेश में 'नीतीश संवाद एवं सुशासन दिवस' के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर पार्टी की ओर से राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से जदयू कार्यकर्ता आम लोगों के बीच पहुंचकर पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए विकास कार्यों, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। पिपरा विधायक रामविलास कामत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने और बिहार की विकास यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में लोगों के बीच जाकर संवाद करेंगे। इस दौरान वर्ष 2005 से पहले और उसके बाद बिहार में हुए बदलावों की चर्चा की जाएगी। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा जाएगा।

विधायक ने बताया कि कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण, मुख्यमंत्री बालिका



साइकिल योजना, पोशाक योजना तथा जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इन योजनाओं से समाज में आए बदलाव और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी चर्चा होगी। विधायक रामविलास कामत ने कहा कि 24 नवंबर को पूरे बिहार में कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया जाएगा। गांव से लेकर शहर तक पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। इस अवसर पर विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जदयू जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरेकान्त झा, युगल किशोर अग्रवाल, अजय कुमार अजनबी, भूषण मंडल, योगेश कुमार कुशवाहा ,ललिता जायसवाल,सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

सीवान के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 8.09 करोड़ का अनुदान, 80 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी

सीवान,एजेंसी। खेती की लागत कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कृषि कार्यालय परिसर में दो दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मेले में जिले के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के साथ-साथ सरकारी अनुदान पर इन्हें खरीदने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत सीवान जिले के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए कुल 8 करोड़ 9 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में 86 प्रकार के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। उद्घाटन के बाद उप निदेशक ने किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण योजना के उद्देश्य, लाभ और विभिन्न कृषि यंत्रों की उपयोगिता की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र, भगवानपुर हाट के वैज्ञानिक सह अभियंता कृष्णा क्षेत्री ने बदलते मौसम की परिस्थितियों में आधुनिक कृषि यंत्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया



कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कृषि कार्यों को आसान बनाने के साथ खेती की लागत भी कम की जा सकती है। मेले के दौरान 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को जिलाधिकारी ने कृषि यंत्रों की चाबी और मैनुअल किट प्रदान कर सम्मानित किया। योजना के तहत अब तक 1,053 कृषि यंत्रों, नौ कस्टम हायरिंग सेंटर, छह स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर और एक फार्म मशीनरी बैंक के लिए परमिट जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार कुल 1,069 परमिट जारी हुए हैं। चयनित किसान परमिट के आधार पर जिले के पंजीकृत विक्रेताओं से कृषि यंत्र खरीद रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन को योजना में विशेष प्राथमिकता दी गयी है। इसके लिए कुल अनुदान राशि का लगभग 33 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है। इसके तहत रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, जीरो टिलेज, रीपर कंबाइन, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर और रीपर बाइंडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों के लिए मैनुअल किट, कतार में बुआई और फसल कटाई के बाद प्रबंधन से जुड़े यंत्रों को भी योजना में शामिल किया गया है। मेले में जिले के पंजीकृत कृषि यंत्र विक्रेताओं ने आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी लगायी है। स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, डिस्क, पावर वीडर, मिनी आटा मिल और मैनुअल एग्रीकल्चर किट किसानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। किसान इन यंत्रों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और अनुदान की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम

पटना,एजेंसी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर होने वाले स्नान को लेकर पटना जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली गई हैं।

गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित गहराई पर बैरिकेडिंग की गई है। खतरनाक एवं अनुपयुक्त घाटों को चिह्नित कर वहाँ बांस-बल्ले में लाल झंडे लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु उन स्थानों पर जाने से बचें। नगर निगम द्वारा सभी प्रमुख घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। गंगा नदी में मोटर बोट एवं नावों के अवैध परिचालन पर रोक लगा दी गई है। नदी में पर्याप्त संख्या में नदी गश्ती दल के साथ एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सभी टीमों को सतत रूप से गतिशील रहकर आवश्यकतानुसार श्रद्धालुओं की सहायता एवं बचाव कार्य के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। भीड़भाड़ वाले प्रमुख घाटों पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। जिले के प्रमुख घाटों पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल एवं पैरामेडिकल टीम की तैनाती की गई है। सिविल सर्जन को पीएमसीएच, एनएमसीएच, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी सहित अन्य प्रमुख अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात मार्ग निर्धारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को निर्धारित यातायात व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षात्मक एवं विधि-व्यवस्था संबंधी तैयारियाँ पूरी रखने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय उपस्थित रहकर पूरी सजगता एवं तत्परता से ड्यूटी करने का निर्देश दिया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

एक नजर

गुवाहाटी में तीसरे नॉर्थ ईस्ट पैरा स्पोर्ट्स मीट में जुटेंगे 700 खिलाड़ी



गुवाहाटी, एजेंसी। गुवाहाटी में 27 से 29 नवंबर तक तीसरे नॉर्थ ईस्ट पैरा स्पोर्ट्स मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के लगभग 700 पैरा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार पड़ोसी देश भूटान और नेपाल के खिलाड़ी भी पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उदयाचल और पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ असम (पीएए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन गुवाहाटी के तीन स्थानों पर किया जाएगा। इनमें सरुसजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उदयाचल और वंद्या इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इस प्रतियोगिता की अनुमोदनकर्ता संस्था है। आयोजकों ने सोमवार को गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रतियोगिता के आधिकारिक शुभंकर, जर्सी और ट्रॉफी का अनावरण किया। इस वर्ष के आयोजन का शुभंकर 'पुहोर' रखा गया है, जिसका अर्थ प्रकाश की किरण है। यह आशा, शक्ति, दृढ़ संकल्प और समावेशिता का प्रतीक है।

नवंबर 2025 में आयोजित दूसरे संस्करण में लगभग 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बार खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर करीब 700 होने की उम्मीद है। भूटान और नेपाल की भागीदारी से प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी मिलेगा। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ असम की मुख्य संरक्षक एवं प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष प्रबंध निदेशक रिंकी भुइयां शर्मा इस आयोजन से मुख्य संरक्षक के रूप में जुड़ी हैं। राजीब डे एसोसिएशन के सचिव और सैयद जरीर हुसैन प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स के उपाध्यक्ष हैं। आयोजकों के अनुसार, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करना तथा समाज में समावेशिता और दृढ़ संकल्प की भावना को बढ़ावा देना है।

शंघाई में खुला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अनूठा संग्रहालय

शंघाई। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को समर्पित संग्रहालय 21 नवंबर को शंघाई में खोला गया। चीनी मुख्यभूमि में अपनी तरह का यह पहला संग्रहालय है, जो रोनाल्डो के करियर और उपलब्धियों को दर्शाता है। सीआर7 संग्रहालय शंघाई नंबर-1 शॉपिंग सेंटर में करीब तीन हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। संग्रहालय के बाहर रोनाल्डो की मशहूर 'सिउ' गोल सेलिब्रेशन मुद्रा में सात मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसे पुर्तगाली फुटबॉलर की दुनिया की सबसे ऊंची पूर्ण आकार की प्रतिमा बताया जा रहा है।

संग्रहालय के अंदर लगी प्रदर्शनी में रोनाल्डो के बचपन से लेकर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सुपरस्टार बनने तक के सफर को दर्शाया गया है। इसके एक हिस्से में लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेलते समय युवा खिलाड़ी के रूप में रोनाल्डो के छात्रावास के कमरे को फिर से तैयार किया गया है। वहां गुलाबी चादर वाले बिस्तर और दीवार पर लिखा संदेश उनके उस सपने की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'एक दिन मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सात नंबर का खिलाड़ी बनूंगा।' संग्रहालय में बैठक कक्ष, क्लबों के ड्रेसिंग रूम और सऊदी अरब के क्लब अल नासर की खिलाड़ियों की सुरंग जैसे अन्य स्थानों की भी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। यहां 50 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इनमें ट्रॉफियां, जर्सी और फुटबॉल जूते शामिल हैं, जिन्हें रोनाल्डो के गृहनगर मदीरा से शंघाई लाया गया है। इनमें से कई वस्तुओं को पहली बार चीनी मुख्यभूमि में प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षणों में रोनाल्डो का 2008 का बैलन डी'ओर पुरस्कार, यूरोपीय चैंपियनशिप की ट्रॉफी और एक मैच में पहने गए फुटबॉल जूते शामिल हैं। संग्रह में रियल मैड्रिड के लिए उनके 350वें गोल की याद में तैयार की गई जर्सी भी रखी गई है। इस पर कोच जिनेदिन जिदान और पूरी टीम के हस्ताक्षर हैं। रोनाल्डो ने शंघाई के इस संग्रहालय के लिए भी एक जर्सी पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। संग्रहालय में गोलकीपिंग की एक इंटरैक्टिव चुनौती भी रखी गई है। इसमें आगंतुक रोनाल्डो के 2018 में युवेंटस के खिलाफ लगाए गए शानदार ओवरहेड किक से प्रेरित आभासी शॉट को रोककर अपनी प्रतिक्रिया क्षमता परख सकते हैं। उस मुकाबले में गोल करने के लिए रोनाल्डो 2.38 मीटर की ऊंचाई तक उछले थे। बताया गया है कि उनके मूल शॉट की गति 71.3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि संग्रहालय में इस चुनौती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आभासी शॉट की गति 28.1 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। शॉपिंग सेंटर का संचालन करने वाले बैलियन समूह के लिए यह संग्रहालय खुदरा कारोबार को सांस्कृतिक, पर्यटन और खेल अनुभवों से जोड़ने की एक और पहल है। इस वर्ष समूह की अन्य पहलों में विश्व कप की थीम पर आयोजित उत्सव भी शामिल रहा है।

केएसएलटीए जनवरी-फरवरी में करेगा बेंगलुरु ओपन और महिला डब्ल्यू100 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी

बेंगलुरु। बेंगलुरु के टेनिस प्रेमियों के लिए नया साल खास होने जा रहा है। कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस संघ (केएसएलटीए) एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में दो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पेशेवर टेनिस प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। इनमें बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 125 और आईटीएफ महिला विश्व टेनिस टूर डब्ल्यू100 शामिल हैं। दो लाख 35 हजार अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाला बेंगलुरु ओपन 2027 चार से नौ जनवरी तक आयोजित होगा। इसके बाद 14 से 21 फरवरी तक एक लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाली आईटीएफ महिला डब्ल्यू100 प्रतियोगिता खेली जाएगी। इन दोनों प्रतियोगिताओं की कुल इनामी राशि तीन लाख 35 हजार अमेरिकी डॉलर होगी। इनके जरिए दुनिया के कई शीर्ष पुरुष और महिला पेशेवर खिलाड़ियों को बेंगलुरु में खेलने का अवसर मिलेगा। बेंगलुरु ओपन ने 2025 में अपना दसवां संस्करण पूरा किया था। यह भारत में एटीपी चैलेंजर टूर की प्रमुख प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुका है। इसे एटीपी चैलेंजर 125 श्रेणी में शामिल किए जाने से इसका स्तर और प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह देश में आयोजित होने वाली उच्च श्रेणी की चैलेंजर प्रतियोगिताओं में से एक है। भारत के कई प्रमुख खिलाड़ियों ने अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु ओपन का मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले एकल खिलाड़ी बनने वाले सुमित नागल ने 2017 में यहां खिताब जीता था और 2024 में उपविजेता रहे थे। प्रजनेश गुणेश्वरन ने भी 2018 में एकल खिताब अपने नाम किया था, जबकि उसी संस्करण में साकेत माइनेनी उपविजेता रहे थे।

वेलिंगटन टेस्ट: मिचेल और फिलिप्स की जुझारू बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड ने भारत को जीत से रोका



वेलिंगटन, एजेंसी। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के आखिरी दिन सोमवार को शानदार धैर्य और संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत से वंचित कर दिया। मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला ड्रॉ करा लिया। अंतिम दिन सुबह के सत्र में दो विकेट गंवाने के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पूरे दिन भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। डेरिल मिचेल (186 गेंदों पर नाबाद 49) और ग्लेन फिलिप्स (126 गेंदों पर नाबाद 26) ने छठे विकेट के लिए 63 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को पांच विकेट पर 239 रन तक पहुंचाया और भारतीय टीम को जीत से दूर कर दिया। वेलिंगटन में सुबह मौसम धीमा और तेज हवाओं वाला था। पहले सत्र में 26 ओवर के खेल में केवल 38 रन बने। इस दौरान रन गति 1.46 रन प्रति ओवर रही। हालांकि, भारत ने दो विकेट हासिल किए और डेवोन कॉनवे तथा रचिन रवींद्र के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 72 रन की जुझारू साझेदारी को तोड़ा। दोनों बल्लेबाज 200 से अधिक गेंदों तक रक्षात्मक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों का सामना करते रहे और बीच-बीच में चौके लगाते रहे।

सत्र शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद वाशिंगटन सुंदर ने हवा की मदद से गेंद को टर्न और ड्रिफ्ट कराते हुए कॉनवे को आउट किया। कॉनवे (165 गेंदों पर 65 रन) के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद उनके पैड से टकराकर उछली और विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। इस बीच, जसप्रीत बुमराह को पिच पर दौड़ने के लिए आधिकारिक चेतावनी भी दी गई। शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए दूसरे घंटे में प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया। लंबे कद के तेज गेंदबाज ने रवींद्र को अपना शिकार बनाया। रवींद्र ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद पिच पर रुककर आई और उनके बल्ले का किनारा लेकर गली में चली गई, जहां केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा। रवींद्र 129 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला और बिना कोई और विकेट गंवाए सत्र समाप्त किया। दूसरे सत्र की शुरुआत में भारत के पास रन आउट का मौका था, लेकिन आकाश दीप मिड ऑन पर गेंद को ठीक से नहीं पकड़ सके और मिचेल को जीवनदान मिल गया। इस प्रयास से कप्तान गिल काफी नाराज दिखे। हालांकि, दो ओवर बाद अंशुल कंबोज ने ब्लंडेल को विकेट के पीछे कैच करा दिया। भारत ने डीआरएस का सहारा लिया और फैसला उसके पक्ष में रहा। इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 176 रन हो गया। भारत ने 83वें ओवर की शुरुआत में दूसरी नई गेंद ली। बुमराह ने एक छोर से और आकाश दीप ने दूसरे छोर से गेंदबाजी शुरू की। पेयजल विश्राम से पहले मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने एक-एक चौका लगाया। फिलिप्स ने आकाश दीप की गेंद को कवर के ऊपर से खेलकर चौका लगाया और न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद प्रसिद्ध ने बुमराह की जगह गेंदबाजी संभाली और मिचेल को परेशानी में डाला। हालांकि, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर क्षेत्ररक्षक नहीं होने के कारण भारत एक आसान कैच का मौका गंवा बैठा। वाशिंगटन की गेंद पर पैड से टकराने के बाद भारत ने फिलिप्स के खिलाफ डीआरएस लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल के कारण वह नॉटआउट रहे। मिचेल और फिलिप्स ने चाय तक बल्लेबाजी जारी रखी और भारत को कोई और सफलता नहीं मिलने दी। दूसरे सत्र में 25 ओवर में 49 रन बने और एक विकेट गिरा। इस दौरान रन गति 1.96 रन प्रति ओवर रही।

इंडियन फुटबॉल लीग का आधिकारिक डेस्टिनेशन पार्टनर बना नागालैंड पर्यटन

नई दिल्ली। इंडियन फुटबॉल लीग ने घोषणा की है कि नागालैंड पर्यटन 2026-27 सत्र के लिए लीग का आधिकारिक डेस्टिनेशन पार्टनर बन गया है। इस साझेदारी के जरिए भारत के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में शामिल नागालैंड और देश की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक इंडियन फुटबॉल लीग को एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य देशभर के फुटबॉल दर्शकों के बीच नागालैंड की विशिष्ट पहचान को पहुंचाना है। इस साझेदारी के तहत नागालैंड पर्यटन लीग के माध्यम से भारत और अन्य देशों के फुटबॉल प्रशंसकों के बीच 'नेचुरली नागालैंड' का प्रचार करेगा। इसके साथ ही इंडियन फुटबॉल लीग को हॉर्नबिल महोत्सव से भी जोड़ा जाएगा। नागालैंड का यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 'महोत्सवों का महोत्सव' एक से 10 दिसंबर 2026 तक कोहिमा के निकट किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित होगा। इस महोत्सव का यह 27वां संस्करण होगा। लीग और महोत्सव के संयुक्त प्रयास से राज्य में अनुभव आधारित पर्यटन और खेल पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे।

इस साझेदारी का स्वागत करते हुए नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉ. नेफ्यू रियो ने कहा, 'हमारा दृष्टिकोण भारत और दुनिया के साथ नागा जीवनशैली की विशिष्टता साझा करना है। इसके साथ ही पर्यटन, खेल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के माध्यम से नए अवसर पैदा करना भी हमारा लक्ष्य है। इंडियन फुटबॉल लीग के साथ यह साझेदारी नागालैंड को अनुभव आधारित पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और कदम है। यहां पर्यटक केवल देखने नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली का अनुभव करने आएंगे। हम एक सार्थक साझेदारी की उम्मीद करते हैं, जो लोगों को एक साथ लाएगी, हमारे युवाओं को प्रेरित करेगी और नागालैंड की कहानी को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाएगी। नागालैंड सरकार के पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने कहा, 'हमें भारत और अन्य देशों में 'नेचुरली नागालैंड' को बढ़ावा देने के लिए इंडियन फुटबॉल लीग का साझेदार के रूप में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। महोत्सवों की भूमि नागालैंड अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, संगीत, खानपान, प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के जरिए अनूठे अनुभव प्रदान करता है। हम विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हॉर्नबिल महोत्सव यानी महोत्सवों के महोत्सव के साथ आईएफएल के जुड़ाव को लेकर उत्साहित हैं।

सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में लगातार तीसरे खिताब के लिए उतरेंगी त्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद

एकल में रक्षिता संभालेंगी भारतीय चुनौती



लखनऊ, एजेंसी। गत चैंपियन त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद मंगलवार से लखनऊ में शुरू हो रहे सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का लगातार तीसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। वहीं, पिछले सप्ताह हांगकांग ओपन में टोक्यो 2020 ओलंपिक की महिला एकल चैंपियन चेन यूफेई को हराकर सुर्खियों में आईं युवा खिलाड़ी रक्षिता रामराज एकल मुकाबलों में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगी। विश्व बैडमिंटन महासंघ की सुपर 300 श्रेणी का यह टूर्नामेंट मंगलवार से रविवार तक बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश बैडमिंटन अकादमी में खेला जाएगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद लगातार तीसरी बार सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। भारतीय जोड़ी ने 2024 में पहली बार यह खिताब जीता था और पिछले साल सफलतापूर्वक इसका बचाव किया था। दोनों 2022 में उपविजेता भी रही थीं। टूर्नामेंट में उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन उनकी मजबूत दावेदारी को दर्शाता है। इस साल की शुरुआत में त्रीसा और गायत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपने प्रदर्शन को और मजबूत किया था।

दूसरी ओर, 19 वर्षीय रक्षिता रामराज हांगकांग ओपन की शानदार लय को घरेलू टूर्नामेंट में भी बरकरार रखना चाहेंगी। भारतीय युवा शटलर ने पिछले गुरुवार को विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज और टोक्यो 2020 ओलंपिक चैंपियन चीन की चेन यूफेई को प्री-क्वार्टर फाइनल में 21-18, 24-22 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। यह मुकाबला सुपर 500 श्रेणी के टूर्नामेंट में खेला गया था। हालांकि, क्वार्टर फाइनल में रक्षिता का सफर थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से हार के साथ समाप्त हो गया था। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला एकल में हिस्सा नहीं ले रही हैं। ऐसे में तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा पर भी घरेलू मैदान पर खिताब जीतने की भारतीय उम्मीदों का दारोमदार रहेगा। विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर काबिज जापान की रिको गुंजी महिला एकल में शीर्ष वरीय खिलाड़ी होंगी। भारतीय चुनौती में अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग, अनमोल खरब और ईशारानी बरुआ भी शामिल हैं। ये सभी घरेलू दर्शकों के सामने प्रभावशाली प्रदर्शन करना चाहेंगी। पुरुष एकल में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। पूर्व विश्व नंबर छह प्रणय को तीसरी वरीयता दी गई है। उनसे आगे सिंगापुर के जेसन तेह और मलेशिया के ली जी जिया हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ली जी जिया इस प्रतियोगिता में भी प्रमुख दावेदार होंगे। आठवीं वरीयता प्राप्त तरुण मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज भी भारत के प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

पुरुष युगल में हरिहरन अम्साकरुनन और एमआर अर्जुन को तीसरी वरीयता दी गई है। वहीं, मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और ओलंपियन तनिषा क्रास्टो शीर्ष वरीयता के साथ भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। हालांकि, भारत को कुछ बड़े खिलाड़ियों की कमी खलेगी। इस महीने की शुरुआत में हायलो ओपन और कुमामोटो मास्टर्स जापान का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन ने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। देश की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी।

भारतीय खिलाड़ियों की सूची

पुरुष एकल

मुख्य ड्रॉ में एचएस प्रणय, तरुण मन्नेपल्ली, किरण जॉर्ज, मिथुन मंजूनाथ, तुषार सुवीर, जिनपॉल सोना, रौनक चौहान, सनीत दयानंद और एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम शामिल हैं।

क्वालीफाइंग दौर में कविन थंगम कविन, ओरिजित चालिहा, प्रणय शेट्टिगार, हमार लालथाजुआला, लक्ष्य शर्मा, नुमैर शेख, सिद्धांत गुप्ता, मनराज सिंह, भरत राघव, आलाप मिश्रा, संस्कार सरस्वत और शाश्वत दलाल चुनौती पेश करेंगे।

महिला एकल

मुख्य ड्रॉ में रक्षिता रामराज, तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग, ईशारानी बरुआ, मालविका बंसोड़, तस्नीम मीर, मानसी सिंह, अनुपमा उपाध्याय, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप, श्रियांशी वालिशेट्टी और अनमोल खरब शामिल हैं।

क्वालीफाइंग दौर में तन्वी पत्री, सूर्या चारिस्मा तमिरी और सामिया इमाद फारूकी उतरेंगी।

पुरुष युगल

मुख्य ड्रॉ में हरिहरन अम्साकरुनन-एमआर अर्जुन, साई प्रतीक-रुबन कुमार रेथिनासाबापति, भार्गव राम अरिगेला-विश्व तेज गोब्बुरु, अभिनाश मोहंती-आयुष पटनायक, कृष्ण प्रसाद गरगा-पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय, विप्लव कुवले-विराज कुवले, अभ्युदय चौधरी-आयुष मखीजा और अच्युतादित्य राव डोड्डावरापु-अर्जुन रेड्डी पोचाना की जोड़ियां खेलेंगी।

क्वालीफाइंग दौर में आर्य ठाकोर-ध्रुव ठाकोर, अमान मोहम्मद-डिंगकू सिंह कोंथौजम, अनुज काले-इयान लोपेज, हिमांशु तिवारी-शशांक छेत्री, कार्तिक राजा बालामुरुगन-पी पार्थ वैद, अशित सूर्या-गणेश विट्टलजी, नितिन कुमार-दक्ष गौतम और सूरज गोआला-निकोलस राज की जोड़ियां उतरेंगी।

महिला युगल

मुख्य ड्रॉ में त्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद, अश्विनी भाट-शिखा गौतम, हृषा दुबे-महरीन रजा, श्रेया बालाजी-प्रणवी नटराजन, समृद्धि सिंह-अमोलिका सिंह सिसोदिया, नयना एस ओएसिस-वर्षिणी विश्वनाथ श्री, रुतपर्णा पांडा-श्वेतापर्णा पांडा, मान्या रहलान-रेशिका उथायसूरियन, गायत्री रावत-मानसा रावत, निशु मलिक-तनु मलिक, अनन्या अरुण-अंजना मणिकंदन, जेनिथ एबिगेल-तारिणी सूरी, अदिति भट्ट-श्रवणी वालेकर, सोनाली सिंह-रितिका ठाकेर, रीवा इवेंजेलिन-वीआर नर्धना, प्रिया कोंजेंगबाम-श्रुति मिश्रा, साक्षी गहलावत-दिव्या आर बालासुब्रमण्यम और अनघा अरविंद पई-नंदिता थॉमस की जोड़ियां शामिल हैं।

क्वालीफाइंग दौर में अक्षिता मनराल-इशिता नेगी, बारुनी पार्श्वल-दिया भीमैय्या, प्रावंधिका राघवन-नेयसा कैरियप्पा, अनघा करंदीकर-पलक अरोड़ा, कर्णिका श्रीस-दीप्ति सतीश, रश्मि गणेश-अमृता प्रमुथेश और इशु मलिक-सिया सिंह की जोड़ियां चुनौती देंगी।

मिश्रित युगल

मुख्य ड्रॉ में ध्रुव कपिला-तनिषा क्रास्टो, रोहन कपूर-रुत्विका शिवानी गड्डे, ध्रुव रावत-मनीषा के, आर्यन सपिया-अमृता प्रमुथेश, मोहित जगलान-लक्षित जगलान, फरोग संजय अमन-जेनिथ एबिगेल, विराज कुवले-रुतपर्णा पांडा, सात्विक रेड्डी कनापुरम-रेशिका उथायसूरियन, हरिहरन अम्साकरुनन-राधिका शर्मा, आयुष मखीजा-अनघा अरविंद पई, अशित सूर्या-अनघा करंदीकर, विमलराज अन्नादुरई-श्रेया बालाजी, हर्षवर्धन कोठारी-आराधना बालचंद्र, भव्या छाबड़ा-अदिति भट्ट और सी लालरामसंगा-कीर्ति मनचला की जोड़ियां खेलेंगी। क्वालीफाइंग दौर में आयुष दास-पूर्वा प्रत्याशा पांडा, वंश देव-इशिता नेगी, विष्णु केदार कोडे-हीरल चौहान, मिथिलेश पी कृष्णन-वर्णा प्रभुनंद और दिव्यम अरोड़ा-श्रवणी वालेकर की जोड़ियां उतरेंगी।

एक नजर

फिनलैंड ने रूसी राजदूत को किया तलब, यूक्रेन पर हमलों और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर जताई नाराजगी

हेलसिंकी,एजेंसी। फिनलैंड ने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर रूस के बढ़ते हमलों और यूरोप में उसकी गतिविधियों के विरोध में सोमवार को रूसी राजदूत को तलब किया। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने रूस की कार्रवाई को खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि फिनलैंड यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर रूस के लगातार बढ़ते हमलों और उसके सैन्य अभियान की कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय ने डेनमार्क, पोलैंड और अन्य यूरोपीय सहयोगी देशों के साथ एकजुटता भी जताई। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन को रूस की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है और मॉस्को को अपना सैन्य अभियान समाप्त करना चाहिए। मंत्रालय ने रूस से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने की मांग भी दोहराई। इस बीच, फिनलैंड के रक्षा मंत्री एंटी हक्कानेन ने आशंका जताई थी कि हेलीकॉप्टर की गतिविधि का संबंध फिनलैंड की खाड़ी में ड्रोन हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुए रूसी मालवाहक जहाज 'स्पार्टा-2' से जुड़े बचाव या निगरानी अभियान से हो सकता है। फिनलैंड ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब 21 नवंबर को देश के हवाई क्षेत्र में एक रूसी हेलीकॉप्टर के संदिग्ध रूप से प्रवेश करने की घटना सामने आई थी। यह घटना दक्षिणी फिनलैंड के तटीय शहर लोविसा के पास हुई। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हेलीकॉप्टर के देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका है। मामले की जांच की जा रही है।

इजराइल में एकता सरकार के पक्ष में बेनेट, आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव

यरुशलम। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और 'ब'याचाद' पार्टी के अध्यक्ष नफ्ताली बेनेट ने लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का समर्थन किया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि ऐसी सरकार में 'याशर' पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाए और बाद में प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व बदला जाए। बेनेट ने नेसेट में सैनिकों के एक समूह से बातचीत के दौरान कहा कि फिलहाल इजराइल में सरकार गठन के तीन संभावित विकल्प हैं। इनमें पहला अरब दलों के समर्थन पर निर्भर सरकार, दूसरा अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के समर्थन वाली सरकार और तीसरा आइजेनकोट के नेतृत्व वाले राजनीतिक गठबंधन तथा लिकुड के बीच एकता सरकार है। तीसरे विकल्प में प्रधानमंत्री पद के लिए बारी-बारी से नेतृत्व की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता तीसरा विकल्प है, जिसमें आइजेनकोट पहले प्रधानमंत्री बनें। हालांकि, बेनेट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रधानमंत्री पद के अगले कार्यकाल में किसे यह जिम्मेदारी मिलेगी। बेनेट ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत है, जिसमें सभी प्रमुख नेता इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) में सैन्य सेवा का समर्थन करते हों और जिनके अपने बच्चे भी सेना में सेवा दे रहे हों। उन्होंने कहा कि जो लोग एक ही टैंक में साथ काम कर सकते हैं, वे देश का संचालन भी मिलकर कर सकते हैं। बेनेट ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करीब दो घंटे तक मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस बैठक से पहले उन्होंने आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन में अपने सहयोगियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, इसके बाद बेनेट ने नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने की संभावना से इनकार करते हुए आइजेनकोट के नेतृत्व में लिकुड को शामिल कर एकता सरकार बनाने के अपने समर्थन को दोहराया।

होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा बहाली के लिए अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी : ईरान



तेहरान। ईरान ने कहा है कि यदि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करता है और तेहरान की शर्तों को स्वीकार करता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य और क्षेत्र में सुरक्षा जल्द से जल्द बहाल की जा सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को यह बात कही। तेहरान में साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बघाई से विदेश मंत्री अब्बास अराघची के उस बयान के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी प्रतिबद्धताएं पूरी होने पर दो घंटे के भीतर जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही थी। सरकारी समाचार एजेंसी 'इरना' के अनुसार बघाई ने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यदि दूसरा पक्ष संबंधित शर्तों को पूरा करता है, तो ईरान भी कम से कम समय में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। बघाई ने कहा कि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं के पालन, अपने अधिकारों की रक्षा और निर्धारित शर्तों को लेकर गंभीर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका की ओर से प्रतिबद्धताएं पूरी किए जाने पर होर्मुज जलडमरूमध्य और क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रवक्ता के मुताबिक, ईरान कोई असामान्य मांग नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अधिकारों के दायरे में आने वाले मुद्दों पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये न तो नई पूर्व शर्तें हैं और न ही अधिकारों से बाहर की मांगें, बल्कि ईरानी जनता के अधिकारों का अभिन्न हिस्सा हैं। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से अलग होने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में बघाई ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इस संबंध में अब तक कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया है। ईरान वर्ष 1970 से इस संधि का सदस्य है।

ईरान का बहरीन में अमेरिकी वायु रक्षा रडार प्रणालियों पर हमले का दावा

मनामा (बहरीन)/तेहरान (ईरान)। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने बहरीन में अमेरिकी वायु रक्षा रडार प्रणालियों पर हमला और होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर एक 'प्रिडेटर' ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने 21 नवंबर को कहा कि ईरान के हमले में एक नागरिक औद्योगिक इकाई को निशाना बनाया गया। इससे वहां आग लग गई और दो लोग घायल हो गए। यह घटना संभावित खतरे की चेतावनी जारी किए जाने के एक घंटे बाद हुई।

अल जजीरा और खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार,आईआरजीसी का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी वायु रक्षा रडार प्रणालियों पर हमला किया और होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर एक 'प्रिडेटर' ड्रोन को मार गिराया। खबरों के अनुसार, 13 नवंबर से बहरीन को फिर से ईरान कीआक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे व्यापक संघर्ष के बीच बहरीन में एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से हमले हो रहे हैं। हाल ही में हुए एक हमले के कारण एक नागरिक ठिकाने पर आग लग गई और बहरीन में दो लोग घायल हो गए। ईरान का कहना है कि वह इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन बहरीन और अमेरिका ने इन दावों का खंडन किया है। बहरीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। बहरीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 13 नवंबर को पहली बार बहरीन ने सिरिक में दो ड्रोन को रोका। मंत्रालय ने बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 13 नवंबर और उसके बाद 15 नवंबर को हुए



हमलों की 'स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी ली है'। आईआरजीसी का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिका के एक 'अर्ली वार्निंग रडार' (शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार) को नष्ट कर दिया । वहीं, अमेरिकी सेंटकॉम ने अपने 'फैक्ट-चेक' बयान में सिरिक पर हुए किसी हमले का कोई जिक्र नहीं किया। सेंटकॉम ने आईआरजीसी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान की ओर से बहरीन की तरफ भेजे गए दो 'वन-वे अटैक ड्रोन' (हमलावर ड्रोन) को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। 15 नवंबर को जारी बहरीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, बहरीन की वायु रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस) ने ईरान के 'कई हवाई हमलों' को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया।

इस बीच, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने दावा किया कि छह ड्रोन ने बहरीन में अल रिफा हेलीकॉप्टर बेस पर स्थित अमेरिकी वायु रक्षा ठिकाने के रडार पर हमला किया। बहरीन ने इस दावे को खारिज कर दिया। बहरीन ने कहा कि किसी भी बहाने से देश की संप्रभुता के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता। 7 नवंबर को बहरीन के निवासियों को 'संभावित खतरे' की चेतावनी जारी किए जाने के कुछ घंटों बाद बहरीन ने घोषणा की कि ईरान ने हमले किए थे। आईआरजीसी ने कहा कि उसने बहरीन में शेख ईसा बेस पर स्थित एक अमेरिकी रडार साइट को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने इस हमले को 16 नवंबर की रात ईरानी हवाई क्षेत्र में अमेरिकी ड्रोन के प्रवेश के जवाब में की गई कार्रवाई बताया। हालांकि, यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे झूठा करार दिया। 18 नवंबर को ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए। बहरीन ने कहा कि उसने इन हमलों को रोक दिया, जबकि कुवैत की सेना ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 'दुश्मन के ड्रोन हमलों' का मुकाबला किया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने 21 नवंबर को बताया कि ईरान के हालिया हमले में एक नागरिक औद्योगिक इकाई को निशाना बनाया गया। हमले दो लोग घायल हो गए। गृह मंत्रालय के अनुसार, घायलों में बहरीन का एक दिव्यांग नागरिक और एक पाकिस्तानी निवासी शामिल हैं। रविवार को गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि बहरीनी नागरिक की हालत स्थिर है, जबकि पाकिस्तानी नागरिक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप कमांडर मेजर जनरल मुस्तफा इजदी ने कहा कि तेहरान के 'दुश्मन' आर्थिक दबाव बढ़ाकर और जनता का भरोसा कम करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान में स्वास्थ्य कर्मचारी को अगवा किया, गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान में धावा बोलकर एक स्वास्थ्य कर्मचारी को अगवा कर लिया है। इस बीच कई इलाकों में गोलीबारी होने की सूचना है। इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। उधर, अगस्त में जबरन गायब किए गए कुछ लोगों के अपने घर पहुंचने बात कही जा रही है। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने मस्तुंग जिले के दश्त जलाब गोंडन इलाके के नदीम बलूच को हिरासत में लेने के बाद गायब कर दिया। यह वाकया 18 नवंबर का बताया गया है। मोइन कुर्द के बेटे नदीम बलूच के गायब होने की जानकारी अब सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मचारी नदीम को मस्तुंग के दश्त जलाब गोंडन इलाके में बेसिक हेल्थ सेंटर से हिरासत में लिया गया। इस बीच बलोचिस्तान के कई इलाकों में गोलीबारी की खबर मिली है। चगाई जिले के दलबंदिन इलाके के धादर में हथियारबंद लोगों ने एक कार्गो बस पर फायरिंग की, जिससे बस ड्राइवर की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद शव और घायलों को डीएचक्यू अस्पताल दलबंदिन में शिफ्ट भेजा गया। गोलीबारी में मारे गए ड्राइवर की पहचान अब्दुल वहीद के रूप में हुई है। वह क्वेटा का रहने वाला है। घायलों में ओबैदुल्ला सुकना नुश्की, फैक और मोहसिन सुकना क्वेटा शामिल हैं। इसके अलावा नुश्की मिल इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और महिलाओं और बच्चों समेत कई यात्री घायल हो गए। दूसरी तरफ, बोलान जिले के मिश्काफ इलाके से दो अज्ञात शव बरामद किए गए हैं।

डीएसपी शेर अहमद के मुताबिक, दोनों शव मिश्काफ के पास मिले, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। केच जिले के मुख्य शहर तुर्बत के शाहरक इलाके में भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, 19 अगस्त, 2026 से गायब चार लोगों को 21 नवंबर को क्वेटा से बरामद किया गया। इनमें दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। नजमा, उमीरा, जाकिर और प्रिसा मस्तुंग जिले के काबू इलाके के रहने वाले हैं। इनको पाकिस्तान की सेना उठा ले गई थी। चारों अपने घर पहुंच गए हैं।

पाकिस्तान के पंजाब में सड़क हादसा, सात लोगों की मौत, दो घायल



लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के उच शरीफ में सोमवार तड़के पत्थरों से लदे एक ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी और उसके ऊपर पलट गया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। बहावलपुर जिला पुलिस अधिकारी राणा अब्दुल वहाब ने इसकी पुष्टि की। डान की रिपोर्ट के अनुसार डेरा गाजी खान से खैरपुर तामेवाली जा रहे मिनी-ट्रक में 16 लोग सवार थे। कोहरे के कारण यह मिनी-ट्रक हाइवे के किनारे रुका हुआ था। पुलिस अधिकारी वहाब ने बताया, 'जब मिनी-ट्रक का ड्राइवर रुकी हुई गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ कर रहा था, तभी पत्थरों से लदा ट्रक उससे टकराकर उसके ऊपर पलट गया। इससे मिनी-ट्रक के यात्री अंदर ही फंस गए। पत्थरों को हटाने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और बचाव दल ने नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि सात लोगों की चोटों के कारण मौत हो गई। रेस्क्यू 1122 के अनुसार बचाए गए लोगों में से दो घायल हैं। वहाब ने बताया कि हादसे के बाद पत्थरों से लदे ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और धूरकोट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इससे पहले इस महीने, पाकपट्टन के पास एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे। 21 अक्टूबर को राजनपुर जिले की रोजहान तहसील में सिंधु हाइवे पर एक यात्री बस सड़क पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और 44 अन्य घायल हो गए थे। 19 अक्टूबर को मुल्तान के बोसान रोड पर हुए एक सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई।

बांग्लादेश में हालात खराब, सरकार ने विपक्ष से चर्चा शुरू की, ढाका और अशांत क्षेत्रों में बीजीबी ने मोर्चा संभाला

ढाका (बांग्लादेश)। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा के बाद से देश में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बम विस्फोट और आगजनी की घटनाओं से पूरा देश दहल उठा है। सरकार हिंसा के लिए हसीना की पार्टी अवामी लीग को दोषी ठहरा रही है। देश के बिगड़े हालात से परेशान प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने विपक्षी दलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आज उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) से चर्चा की। सरकार ने अशांत क्षेत्रों में स्थिति पर नियंत्रण के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों को तैनात किया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बीच नेशनल सिटीजन पार्टी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अतिरिक्त प्रेस सचिव अतीकुर रहमान रुमोन ने बताया कि यह बैठक दोपहर करीब 1:20 बजे शुरू हुई और दो बजे कैबिनेट डिवीजन के कॉन्फ्रेंस रूम में समाप्त हुई। तारिक ने मौजूदा हालात पर एनसीपी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन, वरिष्ठ संयुक्त संयोजक हसनात अब्दुल्ला और संयुक्त संयोजक अकरम हुसैन से वार्ता की।

देश के विभिन्न हिस्सों में जारी हिंसा के कारण बनी मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच हुई बैठक में प्रधानमंत्री के सलाहकार महदी अमीन और जातीय संसद के व्हिप मिया नूरुद्दीन अहमद अपु भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दोपहर करीब 1:04 बजे एक काली माइक्रो बस



से सचिवालय स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। इस बीच सरकार ने राजधानी ढाका और अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए बीजीबी की 98 प्लाटून तैनात की हैं।

इस बल ने प्रमुख प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर मोर्चा संभाल लिया है। शेख हसीना के गृह जनपद गोपालगंज में बीजीबी की दो बटालियन को तैनात किया गया है। इसके अलावा ढाका, गाजीपुर, नारायणगंज, मयमनसिंह, फरीदपुर, चटगांव और कॉक्स बाजार में भी बीजीबी के जवान तैनात किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बीजीबी को जिला प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने बीजीबी को ड्रोन, बॉडी-वर्न कैमरे और अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए हैं। राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के बीच देश के औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारी अशांति ने सरकार के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। ढाका के पास सावर के अशुलिया औद्योगिक क्षेत्र में आज कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दी। बिगड़ते हालात के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 28 फैक्टरियों में छुट्टी घोषित करा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बस में तोड़फोड़ करने और आसपास कारखानों पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ श्रमिकों को रिक्शों से खींचकर पीटा।

एनवीडिया के सीईओ पद पर फिर लौटे जेन्सेन हुआंग, बोर्ड ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी

सांता क्लारा (अमेरिका)। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया ने अपने संस्थापक जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से दोबारा कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त कर दिया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने उन्हें बोर्ड में भी फिर से शामिल करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। हुआंग ने 12 नवंबर को कंपनी के सीईओ और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहीं कोलेट क्रेस अब फिर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में काम करेंगी। एनवीडिया की ओर से जारी बयान के अनुसार, बोर्ड ने हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकें कीं। इसके बाद निदेशकों ने उनके जवाबों और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता पर भरोसा जताया। इस प्रक्रिया के दौरान अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। बोर्ड ने कहा कि मिली जानकारी के आधार पर उसे हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की आशंका नहीं है। बोर्ड के अध्यक्ष हार्वे सी. जोन्स ने कहा कि निदेशक मंडल का मानना है कि हुआंग ही एनवीडिया का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनकी वापसी कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, साझेदारों और ग्राहकों के हित में है। जोन्स ने अंतरिम सीईओ के रूप में जिम्मेदारी निभाने के

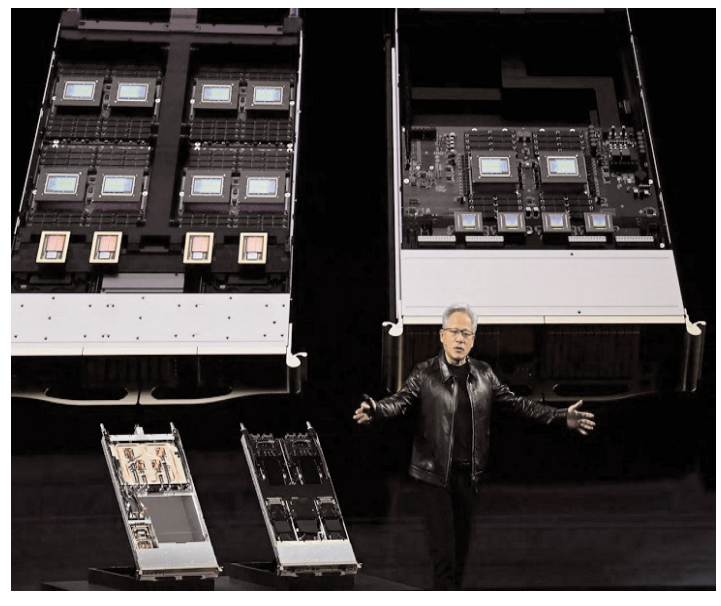

लिए कोलेट क्रेस का भी आभार जताया। हुआंग का इस्तीफा हाल में सामने आई उन मीडिया रिपोर्टों के बाद हुआ था, जिनमें एक विदेशी खुफिया अभियान के तहत उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्टों में एक चीनी कारोबारी महिला के साथ उनके कथित संबंधों और महिला के चीन की खुफिया एजेंसी से संभावित जुड़ाव को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस घटनाक्रम के बाद कंपनी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति गठित कर जांच शुरू की थी।

एनवीडिया ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। कंपनी के अनुसार, हुआंग जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बोर्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग समिति भी बनाई है। इसके साथ ही कंपनी में मुख्य अनुपालन अधिकारी का नया पद सृजित कर इस नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग की वापसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार के पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि हुआंग की एनवीडिया में वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा।

रूस पर यूरोपीय संघ का 22वां प्रतिबंध पैकेज, बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र पर बढ़ेगा दबाव

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों का 22वां पैकेज घोषित किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य रूस की युद्ध के लिए धन जुटाने की क्षमता को सीमित करना और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अलग-थलग करना है। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि रूस के खिलाफ तब तक नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव जारी रहेगा, जब तक वह यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए वास्तविक इच्छाशक्ति नहीं दिखाता। उन्होंने बताया कि नए प्रतिबंधों के तहत रूस के बैंकिंग तंत्र, क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म और भुगतान नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा, उन तीसरे देशों के नेटवर्क पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिनके माध्यम से रूस प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करता है। वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित उपायों के तहत करीब 60 रूसी बैंकों के साथ लेनदेन पर रोक लगाने और उन्हें स्विफ्ट प्रणाली से बाहर करने की बात कही गई है। क्रिप्टोकरेंसी और भुगतान नेटवर्क पर निगरानी तथा कार्रवाई के लिए ईयू ने एक विशेष कार्यबल भी गठित किया है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए यूरोपीय कंपनियों को रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और मरम्मत में सेवाएं देने से रोकने का प्रस्ताव है। इसमें विशेष रूप से तेल रिफाइनरियां शामिल हैं। रूस के कथित छाया बेड़े से जुड़े 70 से अधिक जहाजों को प्रतिबंध सूची में शामिल करने और रूस से जुड़े टैंकरों पर व्यापक पाबंदी लगाने की भी योजना है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने रूसी पूर्व सैनिकों के यूरोपीय संघ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी रखा। उनके अनुसार, यूरोप में रूसी एजेंटों की गैर-पारंपरिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने रूसी पूर्व सैनिकों को यूरोप की सुरक्षा के लिए जोखिम बताया। इसके अलावा, यूरोपीय नागरिकों को रूस की कंपनियों के प्रबंधन निकायों में वरिष्ठ पदों पर बने रहने से रोकने का प्रस्ताव है। खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रतिबंधों का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत रूसी टीमों और खिलाड़ियों के रूस के राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर रोक लगाने, आधिकारिक रूसी प्रतीकों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने और रूसी प्रायोजकों से यूरोपीय खेल एवं सांस्कृतिक संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता सीमित करने की योजना है। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्थन देता रहेगा और रूस के सामने शांति का विकल्प खुला रखेगा।

एक नजर

फ्लिपकार्ट ने एक साल में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बेड़ा दोगुना किया



नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने त्योहारों में अंतिम छोर तक सामान पहुंचाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बेड़ा दोगुना कर 42 हजार कर दिया है। यह संख्या वर्ष 2025 में 20 हजार से अधिक थी। फ्लिपकार्ट के अनुसार फ्लिपकार्ट मिनट्स की डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कुल बेड़े का करीब 77 फीसदी हैं, जबकि 20 फीसदी वाहन उसके बाकी डिलीवरी नेटवर्क में काम कर रहे हैं। कंपनी ने बताया कि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे और गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय संगठन 'द क्लाइमेट ग्रुप' की ईवी100 पहल के तहत 2030 तक अपने पूरे वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने की प्रतिबद्धता के तहत यह विस्तार किया है। फ्लिपकार्ट समूह के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उनके लिए कितने कारगर हैं, यह हमारे डिलीवरी पार्टनर्स खुद तय करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वाहन चलाने की लागत, चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता और वित्तीय सहयोग इस फैसले में सबसे अहमभूमिका निभाते हैं। कुमार ने कहा कि जिन डिलीवरी पार्टनर्स ने पहले इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल किया है, उनमें इसे अपनाने की इच्छा करीब 4 गुना अधिक है। इसलिए हमारा प्रयास है कि उनके लिए पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन आजमाना आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस त्योहारी सीजन में हमारे इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े का दोगुना होना दिखाता है कि जब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना व्यावहारिक और सुविधाजनक होता है, तो डिलीवरी पार्टनर्स बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने विशमास्टर्स और साझेदारों के साथ मिलकर इस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे।

गुरुनानक जयंती पर आज शेयर बाजार में छुट्टी, एमसीएक्स पर शाम के सत्र में होगा कारोबार

नई दिल्ली। गुरु नानक जयंती और प्रकाश गुरपुरब के पावन अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश होने की वजह से 24 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और डेट सेगमेंट सहित सभी प्रकार की ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। इस दिन ट्रेडिंग के साथ-साथ सेटलमेंट हॉलिडे भी रहेगा। टी+1 सेटलमेंट साइकिल के नियम के अनुसार, सोमवार 23 नवंबर को किए गए सौदों, इंट्रा-डे मुनाफे या एफएंडओ पोजीशन से जुड़ी रकम का क्रेडिट निवेशकों के खातों में अब सीधे बुधवार, 25 नवंबर को ही हो सकेगा। हालांकि, कमोडिटी बाजार के निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह का सत्र (सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक) बंद रहेगा, लेकिन शाम पांच बजे के बाद का दूसरा सत्र सामान्य रूप से चालू रहेगा, जिसमें सोना, चांदी और कच्चे तेल जैसे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार किया जा सकेगा। बाजार 25 नवंबर को अपने नियमित समय (प्री ओपनिंग सेशन सुबह नौ बजे और मुख्य कारोबार 9:15 बजे से) पर पुन: खुलेगा। इस सप्ताह निवेशकों को कुल चार कारोबारी दिन (सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार) ही मिलेंगे। वर्ष 2026 में कल की छुट्टी के बाद शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश को छोड़ कर अब साल की अंतिम छुट्टी क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को होगी।



विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सत्तापक्ष ने एसआईआर और सेस को लेकर बनाई रणनीति

रांची,एजेंसी। झारखंड विधानसभा के आगामी 25 और 26 नवंबर 2026 को प्रस्तावित दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर सदन की रणनीति पर चर्चा की। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास से हुई बैठक में खासकर सदन में एसआईआर, खनिज सेस सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब देने पर रणनीति बनाई गई।

बैठक में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम (एमएमडीआर) 2026 और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को सदन में पूरी तैयारी, तथ्यों और आंकड़ों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया, ताकि विपक्ष के सवालों का प्रभावी जवाब दिया जा सके। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और एमएमडीआर एवं एसआईआर को लेकर जनता की चिंताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके आधार पर सदन में बहस और फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर विचार किया गया। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को लेकर सत्ता पक्ष की प्रमुख आपत्ति खनिज संपदा और खनिज युक्त भूमि पर राज्य के राजस्व अधिकारों से जुड़ी है। सरकार को आशंका है कि संशोधन के प्रावधानों से खनिज आधारित राज्यों की सेस और उपकर लगाने की शक्तियां



प्रभावित हो सकती हैं। इससे झारखंड के राजस्व पर असर पड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण में कठिनाई आने की आशंका जताई गई।

बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने भी एमएमडीआर संशोधन पर चिंता जताई। उन्होंने इसे खनिज संपदा वाले राज्यों के हितों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इससे राज्य को हजारों करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान का खतरा है। वहीं, एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी होने और सुनवाई लंबित रहने से वंचित और आदिवासी समुदायों के मताधिकार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता और जरूरत पड़ने पर समय-सीमा बढ़ाने की मांग की। विशेष सत्र में सत्ता पक्ष इन दोनों मुद्दों के साथ राज्य के अधिकार, खनिज राजस्व और मतदाता अधिकारों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ केंद्र की नीतियों पर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। बैठक में सत्तापक्ष के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खास तौर पर मौजूद थे।

योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव जी की जयन्ती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख पंथ के प्रथम गुरू एवं महान संत गुरु नानक देव जी की जयन्ती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी के आदर्शों एवं शिक्षाओं का स्मरण करते हुए सभी के सुख, शान्ति, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी का सम्पूर्ण जीवन सत्य, सेवा, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण की अनुपम प्रेरणा है। उन्होंने मानव सेवा के साथ समाज को समानता, प्रेम और भाईचारे का सन्देश दिया। गुरु नानक देव जी ने जाति, पंथ और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, समान अधिकार और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सन्देश देती हैं कि मानवता की सेवा ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाया। ईमानदारी एवं परिश्रम से आजीविका अर्जित करना, ईश्वर का स्मरण करना तथा अपनी कमाई को जरूरतमंदों के साथ साझा करना उनकी शिक्षाओं का मूल भाव है। उनकी यह शिक्षाएं आज भी समाज में श्रम के सम्मान, परस्पर सहयोग, सामाजिक समरसता और सद्भाव को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देती हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी आडम्बर से दूर रहकर सत्य, सदाचार और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी की जयन्ती हमें अपने जीवन में सेवा, विनम्रता, परोपकार और मानव कल्याण के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करती है। समाज में कोई भी व्यक्ति अभाव, भेदभाव अथवा उपेक्षा का अनुभव न करे, इसके लिए हम सभी को अपने स्तर पर संवेदनशीलता, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं एवं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कामना की कि गुरु नानक देव जी की दिव्य वाणी से सभी का जीवन प्रेम, करुणा और सदाचार से आलोकित हो तथा प्रदेश में सामाजिक समरसता, भाईचारा और लोककल्याण की भावना निरन्तर सुदृढ़ होती रहे।

एनवीडिया ने जेन्सेन हुआंग को फिर से कंपनी का सीईओ नियुक्त किया, कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा

नई दिल्ली। चिप विनिर्माता एनवीडिया के निदेशक मंडल ने बोर्ड के सर्वसम्मत फैसले के बाद जेन्सेन हुआंग को फिर से कंपनी का अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और बोर्ड निदेशक नियुक्त किया है। हुआंग ने 12 नवंबर को कथित विवादों और जांच के बीच पद से इस्तीफा दिया था।

कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि एनवीडिया के निदेशक मंडल ने सोमवार को एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए जेनसन हुआंग को फिर से कंपनी का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। इससे कुछ ही समय पहले बोर्ड ने कंपनी में लौटने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कंपनी ने कहा कि हार्वे सी. जोन्स बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे, जबकि कोलेट क्रेस फिर से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की जिम्मेदारी संभालेंगी। कंपनी ने यह भी कहा कि हुआंग को निशाना बनाने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों की कथित कोशिशों की स्वतंत्र जांच जारी रहेगी।

निदेशक मंडल के प्रमुख हार्वे सी. जोन्स ने एक बयान में कहा, ''बोर्ड का मानना है कि एनवीडिया का नेतृत्व करने के लिए जेनसन सही व्यक्ति हैं और उनकी फिर से नियुक्ति कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों, सहयोगियों और ग्राहकों के हित में है। जेन्सेन हुआंग ने एक बयान में कहा कि वह कंपनी में लौटकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह यह जिम्मेदारी 'बेहद विनम्रता और नए संकल्प के साथ' स्वीकार कर रहे हैं। हुआंग ने सीईओ पद पर बहाल करने के लिए जोन्स और अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस का आभार जताया। उन्होंने कंपनी में उथल-पुथल के दौर में नेतृत्व के लिए एनवीडिया के अन्य कार्यकारी अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।

हुआंग ने कहा, ''मैं अपने कर्मचारियों, शेयरधारकों, उद्योग के प्रमुख लोगों और दुनियाभर के सहयोगियों का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं। सबसे बढ़कर, मैं अपने परिवार के प्यार और सहयोग के लिए उनका आभारी हूं। मैं काम पर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस बीच जेन्सेन हुआंग को फिर से कंपनी का सीईओ बनाने की घोषणा के बाद प्री-मार्केट और शुरुआती कारोबार में एनवीडिया के शेयर 30 फीसदी से 33 फीसदी तक चढ़ गए (लगभग 125.53 डॉलर से बढ़कर 167.04 डॉलर तक), जिससे कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का इज़ाफा हुआ है। दरअसल यह घटनाक्रम हुआंग के उस खुलासे के बाद पैदा हुए विवाद में नया मोड़ है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की थी, जिस पर चीन की जासूस होने का संदेह है। उल्लेखनीय है कि चिप विनिर्माता एनवीडिया कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कैलिफ़ोर्निया के सांता क्लारा में स्थित है।

दिनचर्या और जीवनशैली को सुधारकर फैटी लिवर से मिलेगी निजात : डॉ मांडविया

रांची,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-स्वस्थ भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में मंगलवार को रांची में 'फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान' का भव्य शुभारंभ हुआ। सीसीएल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा विश्व प्रसिद्ध लिवर रोग विशेषज्ञ एवं पद्मभूषण डॉ. एस. के. सरीन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत 2 करोड़ 80 लाख की लागत से तैयार दो अत्याधुनिक स्वास्थ्य जांच वाहनों के माध्यम से रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों की नि:शुल्क फैटी लिवर जांच की सुविधा प्रारंभ की गई। इन वाहनों के माध्यम से लोगों तक जांच की सुविधा पहुंचाई जाएगी, ताकि समय रहते बीमारी की पहचान हो सके और लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने संजय सेठ के इस प्रयास को जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास बताया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज के भागदौड़ भरी जीवन में हम सबो को सबसे पहले अपनी दिनचर्या और जीवनशैली को सुधारने की जरुरत है। इससे 'फैटी लिवर सहित अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए समय पर सोना, समय पर भोजन करना , दैनिक जीवन में पैदल चलना तथा साइकिल चलाने जैसे बातों को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा



कि हम दुनिया की हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। कंप्यूटर और तकनीक के साथ-साथ अपने पैरों को भी चलाइए। जब हम अपने शरीर की जिम्मेदारी लेंगे और जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे, तभी संजय सेठ का यह अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि फैटी लिवर मुक्त रांची की यह मुहिम एक ऐसे दीपक की तरह साबित होगी, जो पूरे देश को इस दिशा में जागरूकता की रोशनी दिखाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। इसी प्रेरणा से फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि रांची लोकसभा क्षेत्र को पूरी तरह फैटी लिवर मुक्त बनाया जाए। पद्मभूषण डॉ. एस. के. सरीन ने कहा कि भारत में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती हैं। इनसे बचाव के लिए समय पर जांच, संतुलित खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी के गंभीर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते जांच और बचाव पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड का पारंपरिक भोजन और यहां की स्थानीय थाली फैटी लिवर से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें अपने पारंपरिक खानपान को अपनाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की जरूरत है।

एनीमिया के मामलों में आई कमी, अधिकांश आयु वर्गों में गंभीर एनीमिया दो प्रतिशत से कम : आईसीएमआर

नई दिल्ली। देश में एनीमिया (खून की कमी) की स्थिति को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नए सर्वेक्षण में राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आईसीएमआर के संपदा सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की तुलना में देश में एनीमिया का प्रसार कम हुआ है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि अधिकांश आयु वर्गों में गंभीर एनीमिया के मामले 2 प्रतिशत से कम हैं और एनीमिया से प्रभावित लोगों में ज्यादातर हल्के स्तर की स्थिति से जूझ रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत आईसीएमआर ने 2023-2025 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण में देश के 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 183 जिलों के 81 हजार से अधिक परिवारों के दो लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया। हीमोग्लोबिन की जांच के लिए 1.7 लाख से अधिक रक्त नमूनों का विश्लेषण किया गया।

सर्वेक्षण की खास बात यह है कि इसमें रक्त की नसों से नमूना लेने की मानक वैज्ञानिक पद्धति और स्वचालित विश्लेषकों के माध्यम से हीमोग्लोबिन का आकलन किया गया। इससे जांच के नतीजों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके अलावा, कुछ प्रतिभागियों में आयरन, फोलेट और विटामिन बी12 की स्थिति के साथ सूजन से जुड़े जैविक संकेतकों की भी जांच की गई।

महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की स्थिति चिंताजनक

सर्वेक्षण के अनुसार, 12 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया का प्रसार 42 प्रतिशत दर्ज किया गया। 10 से 19 वर्ष की किशोरियों में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत रहा, जबकि इसी आयु वर्ग के किशोर लड़कों और 20 से 59 वर्ष के पुरुषों में एनीमिया का प्रसार 22 से 23 प्रतिशत के बीच पाया गया। प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 56 प्रतिशत दर्ज किया गया। सर्वेक्षण में बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है, जिससे इस आयु वर्ग में एनीमिया की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनीमिया की स्थिति उम्र, लिंग, शारीरिक अवस्था और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है। इसलिए सभी वर्गों के लिए एक जैसी रणनीति अपनाने के बजाय उनकी जरूरतों के अनुरूप उपाय जरूरी हैं।

अधिकांश मामले हल्के

एनीमिया के

रिपोर्ट के मुताबिक, एनीमिया से प्रभावित लोगों में हल्के स्तर के मामले बड़ी संख्या में हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया के लगभग आधे मामले हल्के स्तर के हैं। वहीं, किशोर लड़कों, वयस्क और बुजुर्ग पुरुषों में एनीमिया का प्रसार अपेक्षाकृत कम है। इन वर्गों में एनीमिया से प्रभावित लोगों में भी करीब तीन-चौथाई मामले हल्के स्तर के पाए गए। अधिकांश आयु वर्गों में गंभीर एनीमिया का प्रसार 2 प्रतिशत से कम रहा।

एनीमिया का एक प्रमुख कारण

आयरन की कमी

सर्वेक्षण में सामने आया कि महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया के लगभग आधे मामलों के लिए आयरन की कमी जिम्मेदार है। हालांकि, एनीमिया के सभी मामलों को केवल आयरन की कमी से नहीं जोड़ा जा सकता। संक्रमण, हीमोग्लोबिन से संबंधित आनुवंशिक विकार और पुरानी बीमारियों के कारण होने वाली सूजन भी इसके महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन बी12 और फोलेट की कमी एनीमिया से प्रभावित और अप्रभावित दोनों तरह के लोगों में लगभग समान पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि भारत में एनीमिया के कुल मामलों में इन दोनों पोषक तत्वों की कमी का योगदान सीमित है।

आयरन की कमी मुख्य रूप से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में केंद्रित पाई गई। इसके विपरीत किशोर लड़कों, पुरुषों और बुजुर्गों में आयरन की कमी का प्रसार कम रहा। मध्यम और गंभीर एनीमिया से प्रभावित लोगों में आयरन की कमी अधिक पाई गई। ऐसे लोगों की पहचान जांच के माध्यम से कर उचित उपचार और नियमित निगरानी किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि संपदा सर्वेक्षण बच्चों, किशोरों, वयस्कों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बुजुर्गों में एनीमिया की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की तुलना में एनीमिया के प्रसार में कमी आना उत्साहजनक है। सर्वेक्षण से प्राप्त व्यापक आंकड़े एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) की निदेशक डॉ. भारती कुलकर्णी ने कहा कि ये निष्कर्ष एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन के लिए अधिक लक्षित तथा आयु वर्ग के अनुरूप रणनीति बनाने में मददगार होंगे। साथ ही, इससे उन क्षेत्रों की पहचान भी हो सकेगी, जहां आगे और शोध तथा बेहतर निगरानी की जरूरत है।

रिजर्व बैंक ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में बरकरार रखा

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (डी-एसआईबी) की श्रेणी में बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने आज जारी एक अधिसूचना में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को वर्ष 2026 के लिए भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में रखा गया है। आरबीआई ने यह अपडेट 31 मार्च, 2026 तक के डेटा के आधार पर जारी किया है और इनका वर्गीकरण तथा पूंजी नियम 2025 की तरह ही अपरिवर्तित हैं।

आरबीआई ने कहा कि इन तीनों बैंकों को पूंजी संरक्षण बफर के अलावा जोखिम के आधार पर तय परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में अतिरिक्त पूंजी को रखनी होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह समीक्षा 31 मार्च, 2026 तक बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। अधिसूचना में एसबीआई को जोखिम के आधार पर तय परिसंपत्तियों के अनुपात में 0.80 फीसदी अतिरिक्त 'कॉमन इक्विटी



टियर'-1 (सीईटी-1) पूंजी रखनी होगी। एचडीएफसी बैंक के लिए यह जरूरत 0.40 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक के लिए 0.20 फीसदी है। 'कॉमन इक्विटी टियर' बैंक की मुख्य पूंजी होती है। इसमें मुख्य रूप से नकद और शेयर शामिल होते हैं। आरबीआई ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) से जुड़े नियमों की रूपरेखा पहली बार 22 जुलाई, 2014 को जारी किया था। इसमें 28 दिसंबर, 2023 को संशोधन किया गया। इस रूपरेखा के तहत आरबीआई को 2015 से डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम सार्वजनिक करने और उनके प्रणालीगत महत्व के अंक (एसआईएस) के आधार पर उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में रखने की व्यवस्था करनी होती है। आरबीआई के अनुसार एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को क्रमश: 2015 और 2016 में डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक को 2017 में इस श्रेणी में रखा गया था।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)